शुक्रवार
24 जुलाई -2026
वर्ष 10, अंक 320१
पेज 8, मूल्य 2 रुपए
रांची

रांची से प्रकाशित लोकप्रिय दैनिक

अलग पहचान

सत्य की उड़ान

पेज-8

ईरान का मिडिल-ईस्ट में अमेरिकी बेस पर हमला

- बड़ा दावा-जॉर्डन में थाड डिफेंस सिस्टम किया तबाह

तेहरान/वॉशिंगटन (एजेंसी)। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने मिडिल-ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले किए हैं। सेना ने जॉर्डन और कुवैत में यूएस बेस पर ड्रोन और मिसाइल दागी हैं। एजेंसी ने दावा किया कि जॉर्डन में तैनात अमेरिकी थाड (टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस) एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा कुवैत में अमेरिकी रीपर ड्रोन के ऑपरेशन बेस पर भी हमला किया गया। ईरान का कहना है कि ये कार्रवाई हाल के अमेरिकी हमलों के जवाब में की गई है। इससे पहले अमेरिका ने बुधवार रात ईरान में इराक

- कुवैत में ड्रोन ठिकाने को निशाना बनाया, कई हमले किए

बॉर्डर पर स्थित शलमचेह बॉर्डर क्रॉसिंग पर हवाई हमला किया। खुजेस्तान प्रांत के डिप्टी गवर्नर ने बताया कि इस हमले में दो लोगों की मौत हुई है। ट्रम्प ने कहा कि अगर ईरान होर्मुज स्ट्रेट में किसी जहाज पर हमला करता है, तो अमेरिका जवाब में ईरान के पुलों और बिजली घरों पर बमबारी करेगा। इनमें तेहरान के अंदर मौजूद ठिकाने भी शामिल होंगे। यमन के ईरान से जुड़े हूती विद्रोहियों ने शिपिंग कंपनियों को सऊदी अरब के बंदरगाहों से दूर रहने की धमकी दी है। उन्होंने कहा अगर नहीं माना तो हमला होगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक, मौजूदा संघर्ष में अब तक 18 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि सैकड़ों सैनिक घायल हुए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने बताया कि ईरान के साथ युद्ध पर अब तक 37.5 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं।

संसद के बाहर

एनडीए-इंडिया ब्लॉक आमने-सामने

- प्रियंका नारे लगाते हुए एनडीए सांसदों के पास पहुंचीं
- लोकसभा-राज्यसभा दोनों स्थगित

नई दिल्ली (एजेंसी)। संसद के मानसून सत्र के चौथे दिन गुरुवार को संसद भवन के बाहर एनडीए और विपक्ष आमने-सामने आ गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव समेत विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विपक्ष के सामने एनडीए के सांसद भी विरोध प्रदर्शन में उतर गए। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एनडीए सांसद पीएम आवास के बाहर 21 जुलाई को राहुल के धरने का विरोध कर रहे हैं। वहीं इंडिया ब्लॉक नीट पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। प्रदर्शन के दौरान प्रियंका गांधी एनडीए सांसदों के बिल्कुल करीब चली गईं। सुरक्षाकर्मियों ने बीच में आकर उन्हें रोका। संसद के भीतर भी हंगामा जारी रहा। इसके कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 2 बजे लोकसभा में कार्यवाही शुरू हुई तो भारी हंगामा शुरू हो गया। इस पर सदन की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही हंगामे के चलते 3 बजे तक स्थगित कर दी गई। जब दोबारा सदन शुरू हुआ तो सांसदों ने फिर से हंगामा कर दिया। इसके बाद राज्यसभा भी 24 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई।

सीजेपी-सरकार के बीच टकराव जारी

सरकार बोली-कॉकरोच पार्टी को 4 बार बातचीत के लिए बुलाया, प्रस्ताव ठुकराया

सीजेपी ने कहा-नड्डा के घर नहीं जाएंगे, बात करनी है तो वह यहीं आएं

नई दिल्ली (एजेंसी)। सरकार ने गुरुवार को कहा कि वह कॉकरोच जनता पार्टी के साथ किसी भी समय बातचीत के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने दावा किया कि बुधवार दोपहर से अब तक सीजेपी को चार बार प्रस्ताव भेजा गया है। जेपी नड्डा के घर या ऑफिस, कहीं भी बातचीत हो सकती है और दोनों मंत्री इसमें शामिल होंगे। दूसरी ओर सीजेपी ने सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया। सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने कहा

कि अगर सरकार बातचीत करना चाहती है तो जंतर-मंतर आए या प्रदर्शन स्थल के पास किसी न्यूट्रल जगह पर बातचीत करे। सौरव ने कहा-हमें पुलिस ने बताया कि सरकार ने बुलाया है।

बिना सबूत छात्रों को हिंसा से न जोड़ें: गीतांजलि

जंतर-मंतर पर जारी छात्रों के प्रदर्शन के बीच सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. आंगमो ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर छात्रों का पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि एक शिक्षक होने के नाते मीडिया में छात्रों की छवि खराब होते देखना बेहद दुखद है। उनका कहना है कि जंतर-मंतर पर छात्रों का आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है और बिना किसी ठोस सबूत के उन्हें हिंसा से जोड़ना उचित नहीं है। गीतांजलि आंगमो ने लिखा कि यदि दिल्ली के किसी अन्य हिस्से में हिंसा की घटनाएं हुई हैं, तो उन्हें जल्दबाजी में जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन से नहीं जोड़ना चाहिए।

दुखी अन्ना हजारे का अहिल्यानगर में मौन आंदोलन शुरू

देश के जाने-माने समाजसेवी अन्ना हजारे ने अन्ना हजारे ने दिल्ली के छात्रों के समर्थन में अहिल्यानगर में मौन विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। अन्ना हजारे ने गुरुवार को महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में दिल्ली में परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर विरोध कर रहे छात्रों के समर्थन में मौन आंदोलन शुरू किया। वह इस मौके पर बेहद इमोशनल हो गए। वह छात्रों पर बल प्रयोग को लेकर बेहद आहत हैं। हजारे का यह विरोध प्रदर्शन कॉकरोच जनता पार्टी के चल रहे विरोध के बीच हो रहा है, जो परीक्षा पेपर लीक के आरोपों पर जवाबदेही और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। अन्ना हजारे ने एक दिन पहले पीएम मोदी को पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने कहा था कि सरकार हल निकाले। अन्ना ने कहा था कि एक मंत्री के इस्तीफे से सरकार नहीं गिर जाएगी। उनका आशय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ था।

हर छात्र आंदोलन लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं: तस्लीमा

नई दिल्ली (एजेंसी)। जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर बांग्लादेश की लेखिका तसलीमा नसरीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा कि जंतर-मंतर पर जुटे कॉकरोच आंदोलन के प्रदर्शनकारियों को देखकर उन्हें बांग्लादेश के जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन की याद आ गई। उन्होंने कहा कि उस आंदोलन की शुरुआत आरक्षण और मेरिट के मुद्दे से हुई थी, लेकिन बाद में वह सरकार बदलने की मांग तक पहुंच गया। तसलीमा नसरीन ने दावा किया कि बांग्लादेश आज भी उस आंदोलन के बाद की स्थिति की कीमत चुका रहा है।

- बोलीं-बांग्लादेश सा न हो जाए भारत का हाल

लश्कर के 2 आतंकियों के घर ढहाए गए

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में हेड कॉन्स्टेबल की हत्या में थे शामिल

श्रीनगर (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में प्रशासन ने गुरुवार को लश्कर-ए-तैयबा के दो आतंकियों के घर आईईडी लगाकर ध्वस्त कर दिए। यह कार्रवाई लाल चौक में पुलिस बल के हेड कॉन्स्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी की हत्या के एक दिन बाद की गई। अधिकारियों के मुताबिक, जिन आतंकियों के मकान गिराए गए उनमें बिजबेहड़ा के गुरी गांव निवासी आदिल ठोकर और हसनपोरा निवासी हारून गनई शामिल है। मंगलवार दोपहर करीब साढ़े 12 बजे कॉन्स्टेबल कुरैशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमले में ये दोनों आतंकी भी शामिल थे। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग स्थित लाल चौक पर आतंकियों ने इस कायराना वारदात को अंजाम दिया था।

अमरनाथ यात्रा ड्यूटी पर तैनात थे कुरैशी

भारतीय रिजर्व पुलिस और एसओजी से जुड़े हेड कॉन्स्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी अमरनाथ यात्रा ड्यूटी पर तैनात थे। जिस वक्त यह हमला हुआ, उस समय खराब मौसम के कारण अमरनाथ यात्रा अस्थायी रूप से रुकी हुई थी। दोपहर करीब 12.30 बजे आतंकियों ने आतंकियों ने उन्हें बहुत करीब से निशाना बनाया और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। सुरक्षाबलों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलियां चलीं। हमले के बाद आतंकी भाग गए। इस दौरान हेड कॉन्स्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी जख्मी हो गए। उन्हें तुरंत सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शहीद जवान आशिक हुसैन के परिवार में पत्नी और तीन बच्चे हैं। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। दोनों 2018 से सक्रिय बताए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, आदिल ठोकर लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा है, जबकि मौजूदा खुफिया जानकारी के मुताबिक हारून गनई हिजबुल मुजाहिदीन से संबद्ध है। हालांकि, एक अन्य अधिकारी के बयान में दोनों को आतंकी बताया गया है। आदिल ठोकर 2018 में पंजाब के अटारी-वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान गया था। वहां उसने आतंकी शिविरों में प्रशिक्षण लिया और पिछले वर्ष किसी समय फिर जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ कर लौट आया। हमले के बाद सुरक्षा बलों और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पूरे कश्मीर घाटी में व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया।

भाजपा में इस्तीफ़े की नहीं, कुर्सी बचाने की परंपरा; नैतिक जवाब देही पर खड़े हो रहे हैं सवाल - इन्तेखाब आलम

दैनिक अलग पहचान, डेस्क संवाददाता, रांची

नई दिल्ली। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के सदस्य एवं एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन्तेखाब आलम ने कहा कि वर्ष 2014 से केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में किसी केंद्रीय मंत्री द्वारा किसी बड़े जनहित के मुद्दे या सरकारी विफलता की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए इस्तीफ़ा देने का उदाहरण सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि इससे यह धारणा मजबूत होती है कि भाजपा में नैतिक जवाबदेही से अधिक कुर्सी बचाने की संस्कृति को प्राथमिकता दी जाती है।इन्तेखाब आलम ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र में अनेक अवसरों पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पदों से इस्तीफ़ा देते रहे हैं। लोकतंत्र की यही परंपरा

शासन के प्रति जनता के विश्वास को मजबूत करती है।उन्होंने आरोप लगाया कि रेल दुर्घटनाओं, कानून-व्यवस्था से जुड़े गंभीर मामलों, मणिपुर हिंसा और अन्य जनहित के प्रश्नों पर भी संबंधित मंत्रियों ने नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की। उनके अनुसार, इससे सरकार की जवाबदेही और संवेदनशीलता पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं।उन्होंने कहा कि वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग लगातार उठ रही है। उनका आरोप है कि सरकार किसी भी परिस्थिति में इस्तीफ़े की मिसाल कायम नहीं होने देना चाहती। लोकतंत्र में पद से चिपके रहना नहीं, बल्कि नैतिक उत्तरदायित्व निभाना सर्वोच्च मूल्य होना चाहिए। इन्तेखाब आलम ने कहा कि देश यह जानना चाहता है कि जब किसी विभाग के कामकाज पर गंभीर सवाल उठते हैं, तब नैतिकता, संवेदनशीलता और जवाबदेही का पालन कौन करेगा।

दोषियों को सजा के लिए गठित होगी फास्ट ट्रैक कोर्ट

- नीट विवाद के बीच पीएम मोदी का ऐलान, सरकार ऐक्टिव

नई दिल्ली (एजेंसी)। छात्रों द्वारा नीट पेपर लीक को लेकर चल रहे धरना प्रदर्शन के बीच युवाओं और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स लिखा कि पेपर लीक मामलों की त्वरित सुनवाई और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। राज्य/सरकार द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा।

गाजीपुर में 51 लाइसेंस पर 145 हथियार!

- सपा सांसद अफजल भी फंसे, मुख्तार के गिरोह की थी साजिश

गाजीपुर (एजेंसी)। गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के सांसद अफजल अंसारी हथियारों के लाइसेंसों में की गई गड़बड़ी के मामले में फंस गए हैं। यहां पर 51 शस्त्र लाइसेंसों पर 145 हथियारों की खरीद-बिक्री की गई है। यह करतूत दो क्लर्कों की मदद से की गई है। इस मामले में बाहुबली नेता और माफिया रहे मुख्तार अंसारी के भाई सांसद अफजल अंसारी और कुख्यात आईएस-191 गिरोह के सदस्य कथित रूप से शामिल रहे हैं। पुलिस ने अफजल और दो लिपिकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, जिले के अभिलेखागार से शस्त्र लाइसेंस और उसकी खरीद-बिक्री से जुड़ी पत्रावली गायब कर दी गई है।

आईएस-191 गिरोह के सदस्यों के हैं हथियार लाइसेंस

एसपी डॉ ईरज राजा के अनुसार माफिया सरगना रहे मुख्तार अंसारी और उसके परिवार के लोगों ने आईएस-191 गिरोह के सदस्यों व सहयोगियों के नाम से जारी किए गए हथियारों के 51 लाइसेंसों की खरीद-बिक्री की थी। इसकी जांच दो महीने तक चली। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों के अलावा दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश के जिलाधिकारी कार्यालयों पर जाकर जांच की।

ओड़िया कविता में राष्ट्रवादी चेतना भुवनेश्वर

उड़िया। देशभक्ति और भावनात्मक भावना जो एक देश को वफ़ादारी, सहानुभूति और सांस्कृतिक रिश्तों से बांधती है और लोगों में एकता की भावना पैदा करती है, वही राष्ट्रवाद है। इस मामले में ओड़िया साहित्य में उत्कलदीपिका, बालेश्वरर खबरवभाका, संबलपुर हितैषिनी, उत्कलपुत्र, पुरुषोत्तम चंद्रिका और उत्कल साहित्य जैसी पत्रिकाओं की भूमिका भी यादगार है। राधानाथ रे, फकीरमोहन साहबी, मधुसूदन दास, गंगाधर मेहर, नंदकिशोर बाला, कुंतलकुमारी सावत, सत्यबंधी साधक और दूसरे कवियों ने अपनी कविताओं में इतिहास के लिए प्यार, मातृभूमि के लिए प्यार, भाषा के लिए प्यार, क्षेत्रवाद के लिए प्यार और सबसे बढ़कर मुक्ति आंदोलन के लिए अपना समर्थन दिखाया है, जिससे

उनकी राष्ट्रीय चेतना को एक सच्ची पहचान मिली है, यह बात साहित्य अकादमी और ओडिशा साहित्य अकादमी के मिलकर किए गए प्रयासों से 22 जुलाई 2026 को सुबह 11.00 बजे भुवनेश्वर के संस्कृति भवन कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित 'ओड़िया कविता में राष्ट्रीय चेतना' नाम के एक दिन के सिंपोजियम में बुलाए गए मेहमानों और स्पीकर्स ने कही। उद्घाटन सत्र में साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी डॉ. वरुण गुलाटी ने इसके अप्रोच के बारे में बात की। एक स्पीच दी। जाने-माने वक्ता और साहित्यकार और ओड़िया भाषा, साहित्य और संस्कृति विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी, श्रीयुत देबप्रसाद दाश ने ओड़िया कविता में राष्ट्रवादी चेतना विषय पर अपनी उद्घाटन स्पीच दी। ओडिशा साहित्य अकादमी के सचिव डॉ. चंद्रशेखर होता ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और भाषण देते हुए कहा कि ओडिया राष्ट्र के जीवन को व्यवस्थित करने और ओडिया कविता में राष्ट्रवादी चेतना में चिर्णमस्य साधकों का योगदान अविस्मरणीय है। प्रख्यात अनुवादक और सुलेखक डॉ. शकुंतला धोलेरासिंघा ने चर्चा के विषय पर मुख्य भाषण दिया। साहित्य अकादमी और ओडिया सलाहकार परिषद के संयोजक डॉ. गौरहरि दास ने अध्यक्ष के रूप में भाग लिया और पहले चर्चा किए गए सम्मानित व्यक्तियों के भाषणों के बारे में समय पर जानकारी प्रदान की और यह भी चर्चा की कि ओडिया का राष्ट्रीय जीवन गाथक कविता और विभिन्न व्याख्यात्मक कविताओं में कैसे परिलक्षित होता है। उन्होंने इस पर अपना भाषण प्रस्तुत किया। श्रीयुक्त क्षेत्रबासा नायक ने साहित्य अकादमी की ओर से धन्यवाद प्रस्ताव रखा। पहले सत्र में डॉ. बासुदेव दास की अध्यक्षता में, अरुण कुमार साहू, विश्वरंजन दास और नारायण पंडा ने प्रोफेसर उदयनाथ साहू की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अध्यक्ष के रूप में भाग लिया। दूसरे सेशन में प्रोफेसर उदयनाथ साहू की अध्यक्षता में डॉ. रमेश चंद्र बेहरा और रंजीत परिदा आदि ने हिस्सा लिया और पेपर पेश किए। आखिर में ओडिशा साहित्य अकादमी के जॉइंट सेक्रेटरी श्रीयुक्त संजय कुमार कुकरालसिंह ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया। इस मौके पर साहित्य अकादमी की तरफ से एक बुक एग्जीबिशन और सेल का आयोजन किया गया।

संक्षिप्त समाचार

जगन्नाथपुर के बुढ़ाकमान गांव में जंगली हाथी ने ग्रामीण की ले ली जान,

जगन्नाथपुर, एजेंसी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर प्रखंड अंतर्गत बुढ़ाकमान गांव में मंगलवार देर रात जंगली हाथी के हमले में एक ग्रामीण की मौत हो गई। मृतक की पहचान चंद्र मोहन सिंकु के रूप में हुई है। घटना के बाद पूरे गांव में शोक और दहशत का माहौल बना हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार, मंगलवार रात करीब 12 :30 बजे गांव में जंगली हाथी के घुसने की सूचना मिलते ही ग्रामीण शोर मचाकर उसे भगाने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान चंद्र मोहन सिंकु अपने घर से कुछ दूरी पर हाथी को देखने के लिए बाहर निकले। तभी अचानक उनका सामना एक दंतैल हाथी से हो गया। हाथी ने उन पर हमला कर अपने पैरों से कुचल दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से घायल चंद्र मोहन सिंकु को जगन्नाथपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद ग्रामीणों में भय का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में जंगली हाथियों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है, लेकिन वन विभाग की ओर से पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी नहीं की जा रही है। देर रात हुई इस घटना ने लोगों में असुरक्षा की भावना और बढ़ा दी है। घटना के बाद जिला परिषद सदस्य मानसिंह तिरिया ने वन विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि घटना की सूचना देने के लिए उन्होंने चाईबासा रेंजर, नोआमुंडी फॉरेस्टर और क्षेत्रीय वनरक्षक से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। उन्होंने यह भी बताया कि घटना के समय गांव में बिजली आपूर्ति बाधित थी, जिससे हाथी की मौजूदगी का समय रहते पता नहीं चल सका। उनका कहना है कि यदि बिजली रहती तो संभवत : इस हादसे को टाला जा सकता था।

द प्राइड ऑफ ट्राइब ने गुवाहाटी में लहराया परचम, टीपीओटी अब झारखंड में करेगा नेशनल ट्राइबल फैशन शो

रांची, एजेंसी। भारत की समृद्ध आदिवासी संस्कृति, पारंपरिक कला और हथकरघा विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में द प्राइड ऑफ ट्राइब (टीपीओटी) ने एक और उपलब्धि हासिल की है। नॉर्थ इस्ट इंटरनेशनल फैशन वीक (एनइआइएफडब्ल्यू) 2026 असम के गुवाहाटी में अपने शानदार डेब्यू के साथ टीपीओटी ने झारखंड सहित देशभर की आदिवासी विरासत को राष्ट्रीय मंच पर प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। इस फैशन शो की बड़ी विशेषता जनजातीय सोहराई कला और स्वदेशी हथकरघा वस्त्रों का आकर्षक प्रदर्शन रहा। पारंपरिक आदिवासी कलाओं को आधुनिक डिजाइन के साथ प्रस्तुत कर टीपीओटी ने यह संदेश दिया कि आदिवासी संस्कृति केवल अतीत की धरोहर नहीं, बल्कि भविष्य की प्रेरणा भी है। झारखंड की दो प्रतिभाशाली आदिवासी जूनियर मॉडल अंजलि लकड़ा व लक्ष्मी तिग्गा ने फ्रेशर ग्रुप में पहली बार इतने बड़े राष्ट्रीय मंच पर आत्मविश्वास के साथ रैंप वॉक कर ध्यान आकर्षित किया। कार्यक्रम में एनइआइएफडब्ल्यू के संस्थापक प्रशांत घोष भी उपस्थित रहे। सराहना करते हुए आगामी नेशनल ट्राइबल फैशन शो के आयोजन में अपना पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। टीपीओटी की टीम लीड कांति गाड़ी ने कहा यह केवल एक फैशन शो नहीं, बल्कि हमारी पहचान, स्वाभिमान और आजीविका का अभियान है। एनइआइएफडब्ल्यू 2026 में मिली शानदार सफलता और सकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद द प्राइड ऑफ ट्राइब अब झारखंड में नेशनल ट्राइबल फैशन शो आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। इस मंच का उद्देश्य आदिवासी कारीगरों, बुनकरों, डिजाइनरों, मॉडलों, मेकअप आर्टिस्टों, फोटोग्राफरों, टेक्सटाइल विशेषज्ञों व कलाकारों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर उपलब्ध कराना है।

मजदूर की बेटी पूनम ने नीट में मारी बाजी, सरकार उठायेगी पढ़ाई का खर्च

धनबाद, एजेंसी। एसएसएलएनटी सीएम उत्कृष्ट गर्ल्स विद्यालय की छात्रा रही पूनम ने नीट परीक्षा में शानदार सफलता हासिल कर अपने परिवार, स्कूल और पूरे धनबाद का नाम रोशन किया है। जिला प्रशासन ने पूनम की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने की घोषणा की है। धनबाद की रहने वाली पूनम कुमारी ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में 582 अंक, 99।1375 परसेंटाइल और ऑल इंडिया रैंक 16,972 हासिल की है। पूनम के पिता धरमू गोराई दिहाड़ी मजदूर हैं, जबकि मां पीपू देवी गृहिणी हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होने के बावजूद पूनम ने लगातार मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल किया। इससे पहले वह सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से पढ़कर सीबीएसइ 12वीं बोर्ड परीक्षा में 97।4 प्रतिशत अंक लाकर धनबाद जिला टॉपर भी रह चुकी हैं। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन ने मंगलवार को पूनम को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में नीट में सफल होने पर सम्मानित किया।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग की समीक्षा बैठक,

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिए कई निर्देश

रांची, एजेंसी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग के कार्यों एवं विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। झारखंड मंत्रालय में हुई इस बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, विभागीय सचिव पूजा सिंघल, विशेष सचिव सुनील कुमार सिंह, निदेशक आईटी माधवी मिश्रा, सीईओ जैप-आईटी चंदन कुमार आदि अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में ई-गवर्नेंस परियोजनाओं, डिजिटल सेवाओं के विस्तार, साइबर सुरक्षा, डेटा प्रबंधन, सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण तथा आईटी आधारित नवाचारों की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान डिजिटल झारखंड विजन 2029 पर विशेष चर्चा हुई, जिसमें अधिकारियों ने आईटी पार्क निर्माण की रूपरेखा एवं साइट प्लान प्रस्तुत किया और मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

समीक्षा बैठक में चीफ मिनिस्टर डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के विकास पर भी विचार-विमर्श हुआ, जिसके माध्यम से सभी विभागों के डेटा एवं पोर्टलों का एक साथ आकलन किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि प्रत्येक विभाग एवं प्रत्येक जिले में आईटी अधिकारियों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता के साथ कार्य करते हुए यह सुनिश्चित करना होगा बढ़े। उन्होंने सभी विभागों के डेटा को एकीकृत करने पर जोर दिया, जिससे बेहतर समन्वय और निर्णय प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके। बैठक में झारखंड स्टेट डेटा सेंटर को सुदृढ़ बनाने तथा डेटा की सुरक्षा एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने पर भी चर्चा हुई।

डिजिटल झारखंड का सपना साकार करने पर जोर : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि डिजिटल झारखंड का सपना तभी साकार होगा, जब तकनीक का लाभ राज्य के दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों तक प्रभावी रूप से पहुंचे। इसके लिए आवश्यक है डिजिटल सेवाओं का विस्तार अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भी नागरिक सूचना और सेवाओं से वंचित न रहे। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता के साथ कार्य करते हुए यह सुनिश्चित करना होगा कि तकनीक आम लोगों के जीवन को सरल, सुलभ और सुगम बनाए।

उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीकों के समुचित उपयोग से न केवल प्रशासनिक कार्यप्रणाली अधिक सुदृढ़ और जवाबदेह बनेगी, बल्कि सेवा वितरण प्रणाली में भी गति आएगी। मुख्यमंत्री ने झारखंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड के कार्यों की समीक्षा करते हुए राज्य के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यापक मैपिंग कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी क्षेत्रों में डिजिटल संसाधनों की वास्तविक स्थिति का आकलन कर योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्य सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने आगामी तीन वर्षों में राज्य के सभी पंचायतों को 5त नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित करने को कहा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों तक भी उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल कनेक्टिविटी उपलब्ध हो सके।

इस बैठक में भारतनेट फेज-3, कनेक्टिंग झारखंड तथा स्टेट वाइड नेटवर्क जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की भी विस्तृत समीक्षा की गई। जैप-आईटी की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने संस्थान में रिक्त पदों को भरने के निर्देश दिए, ताकि विभागीय कार्यों की गति और दक्षता में वृद्धि हो सके। इसके साथ ही पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी नेटवर्क, ड्रोन तथा सैटेलाइट आधारित परियोजनाओं की प्रगति की भी विस्तृत समीक्षा की गई और इन परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने पर जोर दिया गया। उन्होंने राज्य के सभी विभागों के डेटा को एक समान प्रारूप में केंद्रीकृत करने तथा अत्याधुनिक साइबर सुरक्षा तंत्र विकसित करने पर जोर देते हुए नियमित सुरक्षा ऑडिट सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इंटरनेट शैडो क्षेत्रों की पहचान करने का निर्देश : राज्य में डिजिटल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जहां नेटवर्क उपलब्ध नहीं है या अत्यंत कमजोर है, वहां पहचान कर चरणबद्ध तरीके से नेटवर्क विस्तार करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राज्य का कोई भी गांव, कस्बा या शहर डिजिटल सेवाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक क्षेत्र तक 5त इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने हेतु ठोस एवं समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने को कहा, ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनिक सेवाओं एवं डिजिटल शासन को नई गति मिल सके।

मुख्यमंत्री ने सभी जिला न्यायालयों में उच्च गुणवत्ता वाले साउंड सिस्टम स्थापित करने के सुझाव दिए, ताकि न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं एवं वादकारियों के बीच संवाद अधिक स्पष्ट, सुगम और प्रभावी हो सके तथा न्यायिक कार्यों में दक्षता सुनिश्चित की जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का विकास केवल आईटी पार्क निर्माण तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि एक समग्र एवं सुदृढ़ आईटी इकोसिस्टम विकसित किया जाना आवश्यक है।इसके अंतर्गत आईटी उद्योगों को प्रोत्साहन, स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा, नवाचार एवं अनुसंधान को समर्थन, कौशल विकास को सुदृढ़ करना तथा व्यापक स्तर पर रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित करना शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में निवेश आकर्षित करने हेतु प्रभावी एवं व्यावहारिक कार्ययोजना तैयार की जाए, जिससे युवाओं के लिए आईटी क्षेत्र में नए अवसर उपलब्ध हो सकें।

मुख्यमंत्री से खेल सचिव, खेल निदेशक एवं मेजर जनरल ने की मुलाकात, डूरंड कप में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने हेतु दिया निमंत्रण

दैनिक अलग पहचान, डेस्क संवाददाता, रांची

रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के सचिव मुकेश कुमार, खेल निदेशक छवि रंजन, जनरल ऑफिसर कमांडिंग-23 आईबीजी मेजर जनरल सज्जन सिंह मान, डूरंड कप के नोडल अधिकारी कर्नल हेम चंद्रा तथा सहायक नोडल अधिकारी मेजर आनंद प्रकाश ने कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को रांची में 26 जुलाई 2026 से आयोजित होने वाले 135वें संस्करण डूरंड कप-2026 के उद्घाटन समारोह एवं उद्घाटन मैच में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहिबगंज द्वारा नशामुक्ति एवं कानूनी जागरूकता विषय पर निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिता का सफल आयोजन

दैनिक अलग पहचान, डेस्क संवाददाता, रांची /

साहिबगंज झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (JHALSA), रांची के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहिबगंज अखिल कुमार के मार्गदर्शन में संचालित 90 दिवसीय कानूनी जागरूकता अभियान के अंतर्गत आज कस्तूरबा विद्यालय, साहिबगंज में छात्राओं के बीच 'नशामुक्ति' विषय पर निबंध लेखन एवं चित्रकला प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में नशामुक्त समाज के निर्माण, कानूनी जागरूकता तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना था। प्रतियोगिता में छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए नशामुक्ति, बाल अधिकार एवं मानव तस्करी जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक विषयों पर अपने विचारों एवं रचनात्मक प्रतिभा का प्रभावशाली प्रदर्शन किया।झ निबंध लेखन प्रतियोगिता में कक्षा 9 की छात्रा सपना कुमारी ने प्रथम, सोनम कुमारी ने द्वितीय तथा रुचि कुमारी

ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं चित्रकला प्रतियोगिता में अर्चना, नन्दिनी एवं काजल कुमारी ने संयुक्त रूप से प्रथम, डॉली कुमारी, अंजली खातून एवं अनुश्का कुमारी ने संयुक्त द्वितीय तथा प्रगति कुमारी, सुनीता कुमारी एवं स्वर्णलता सोरेन ने संयुक्त तृतीय स्थान प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट परिचय दिया।इस अवसर पर छात्राओं द्वारा मानव तस्करी जैसे गंभीर सामाजिक अपराध पर प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया गया, जिसने उपस्थित सभी लोगों को जागरूक एवं भावुक किया। कार्यक्रम के दौरान डिप्टी चीफ एलएडीसी कामिनी शर्मा ने छात्राओं को POCSO Act, Good Touch-Bad Touch तथा बाल सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। वहीं डिप्टी चीफ एलएडीसी रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने बाल श्रम एवं मानव तस्करी की रोकथाम के संबंध में विस्तृत जानकारी साझा की। असिस्टेंट एलएडीआरओ श्री रतन कुमार ने छात्राओं को शिक्षा के अधिकार अधिनियम एवं नालसा हेल्पलाइन 15100 की उपयोगिता एवं सेवाओं के बारे में विस्तार से अवगत कराया।

धनबाद रोजगार मेले में पहुंची 19 कंपनियां, 2000 से अधिक वैकेंसी, दुबई तक नौकरी का मौका

धनबाद, एजेंसी। जिले के बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से बुधवार को जिला नियोजन कार्यालय परिसर में श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में 19 से अधिक नामी कंपनियों ने भाग लिया और 2000 से ज्यादा रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए युवाओं का चयन किया गया। खास बात यह रही कि इस बार देश के कई बड़े शहरों के साथ-साथ दुबई में नौकरी देने वाली कंपनियां भी मेले में शामिल हुईं।

रोजगार मेले में धनबाद, रांची, बेंगलुरु, दिल्ली और चेन्नई समेत विभिन्न शहरों से आई कंपनियों ने तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों के लिए आवेदन स्वीकार किए। बड़ी संख्या में पहुंचे युवाओं ने कंपनियों के प्रतिनिधियों से बातचीत की, अपने दस्तावेज जमा किए और साक्षात्कार में हिस्सा लिया। कई अभ्यर्थियों का प्रारंभिक चयन मौके पर ही कर लिया गया, जबकि अन्य को अगले चरण की प्रक्रिया के लिए बुलाया गया।

कार्यक्रम के दौरान सहायक निदेशक पदमा कुमारी ने कहा कि विभाग का प्रयास युवाओं को उनकी योग्यता और कौशल के अनुरूप रोजगार

उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि इस रोजगार मेले में 19 से अधिक कंपनियां 2000 से ज्यादा रिक्तियां लेकर पहुंची हैं। इनमें देश के विभिन्न औद्योगिक शहरों के अलावा दुबई में रोजगार उपलब्ध कराने वाली कंपनियां भी शामिल हैं। उन्होंने युवाओं से ऐसे रोजगार मेलों में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की है।

मेले में पहुंचे अभ्यर्थियों ने भी इस पहल को उपयोगी बताते हुए कहा कि एक ही मंच पर कई कंपनियों से सीधे संपर्क करने और इंटरव्यू देने का अवसर मिलने से नौकरी तलाशने की प्रक्रिया आसान हो गई है। उनका मानना है कि इस तरह के आयोजन नियमित रूप से होने चाहिए, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सके।

जिला नियोजन कार्यालय में आयोजित यह रोजगार मेला न केवल युवाओं के लिए रोजगार का माध्यम बना, बल्कि उन्हें देश और विदेश की कंपनियों तक पहुंचने का भी अवसर प्रदान किया गया। इससे जिले के रोजगार परिदृश्य को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

NEET-JPSC विवाद पर रांची में हंगामा, भाजपा-कांग्रेस कार्यकर्ताओं में पत्थरबाजी, पत्रकार घायल

दैनिक अलग पहचान, डेस्क संवाददाता, रांची /

रांची: NEET और JPSC में कथित गड़बड़ियों को लेकर रांची में भाजपा और कांग्रेस के बीच टकराव सड़क पर आ गया। बुधवार को भाजपा के कांग्रेस कार्यालय घेराव के जवाब में गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय का घेराव किया।हरमू मैदान से जुलूस निकालकर पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हरमू रोड स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय के पास आमने-सामने की स्थिति बन गई। दोनों ओर से जमकर नारेबाजी हुई और पत्थर, टमाटर, अंडे व पानी की बोतलें फेंकी गईं। इस दौरान एक पत्रकार भी घायल हो गया। कांग्रेस कार्यकर्ता हृश्वश्वञ्ज पेपर लीक को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और JPSC में गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने एक बैरिकेड तोड़ दिया, लेकिन पुलिस ने दूसरी बैरिकेड पर रोक दिया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज कर दोनों पक्षों को अलग किया।सुरक्षा के मद्देनजर भाजपा कार्यालय के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल और रैपिड रिस्पांस टीम तैनात की गई थी।

कांग्रेस का कहना है कि परीक्षाओं में गड़बड़ी से युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। वहीं भाजपा ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार जवाबदेही से बच रही है।

झारखण्ड 6:00 PM, SIR बुलेटिन

दैनिक अलग पहचान, डेस्क संवाददाता, रांची

रांची। 2026 के मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या-2,64,63,236

(A). मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराने की कुल संख्या-2,61,72,859(98.90%)

(B). मतदाताओं द्वारा भरे हुए एवं हस्ताक्षर किए हुए इन्यूमरेशन फॉर्म के डिजिटाइजेशन की कुल संख्या (इन मतदाताओं का नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाले ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल)-2,05,07,656 **(C).** वापस प्राप्त नहीं होने वाले इन्यूमरेशन फॉर्म की कुल संख्या-17,56,154 I.मृत मतदाताओं की कुल संख्या-4,99,354 (1.89%) II. पता लगाने योग्य नहीं/ अनुपस्थित मतदाताओं की कुल संख्या-2,62,262 (0.99%) III. स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं की कुल संख्या-7,81,934 (2.95%) IV.अन्य स्थानों पर पहले से ही नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या-2,07,017(0.78%) V.इन्यूमरेशन फॉर्म हस्ताक्षर करने से इनकार करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या-5,587

गढ़वा में पत्थर खनन से परेशान ग्रामीणों ने विधायक से लगाई गुहार

गढ़वा, एजेंसी। जिले के रंका प्रखंड क्षेत्र में मौजूद क्रशर प्लांट संचालन के खिलाफ ग्रामीण गोलबंद हो गए हैं। क्योंकि क्रशर और माइनिंग से ग्रामीणों की खेती और जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जिसके बाद ग्रामीणों की मदद के लिए बीजेपी विधायक ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि नियमों की अनदेखी करके क्रशर संचालक को माइनिंग का लाइसेंस दिया गया है। इस खदान की वजह से ग्रामीणों का गांव में रहना मुश्किल हो गया है। खदान से निकलने वाले डस्ट और बालास्टिंग की वजह से लोग पलायन को मजबूर हैं।

वहीं रंका प्रखंड के पिंडरा गांव के ग्रामीणों ने गढ़वा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी को गांव में बुलाकर अपनी परेशानी बताकर न्याय की गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने बताया कि गासेदाग गांव में संचालित क्रशर प्लांट से उन्हें काफी परेशानी हो रही है। क्रशर प्लांट के पास सिंचित भूमि से ऊपर बांध बना दिया है,

जिससे कई ग्रामीणों को खेती करने में दिक्कत हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि समस्या के समाधान की मांग करने पर क्रशर संचालक द्वारा धमकी दी जा रही है। जिसके बाद कुछ ग्रामीणों ने 20 जुलाई को रंका थाने में लिखित में शिकायत भी दर्ज कराई है। वहीं विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने ग्रामीणों की आपबीती सुनने के बाद कहा कि ये गंभीर मामला है। ग्रामीणों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।

विधायक ने कहा कि डीसी एवं एसपी से मिलकर बात करूंगा। ग्रामीणों को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए। साथ ही मामले को विधानसभा में भी उठाऊंगा। जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई होनी चोहिए। विधायक ने आरोप लगाते हुए बताया कि रंका में कई जगहों पर नियमों का उल्लंघन करके क्रशर संचालकों को एनओसी दी गई है, जो गलत है क्योंकि इसका खामियाजा स्थानीय ग्रामीण भुगत रहे हैं।

वहीं जिले के पिंडरा स्थित क्रशर संचालक अंजनी सिंह ने बुधवार को पत्रकार वार्ता करके गढ़वा विधायक सत्येन्द्रनाथ तिवारी एवं उनके प्रतिनिधि रिंकू तिवारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में व्यवसाय करना कठिन बना दिया गया है और उन पर रंगदारी देने का दबाव बनाया जा रहा है। अंजनी सिंह ने आरोप लगाते हुए बताया कि गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में काम करना है, तो 'विधायक' को पैसा देना होगा, तभी काम करने दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक और उनके प्रतिनिधि रिंकू तिवारी 'रंगदारी' मांगते हैं। सरकार को हम लोग नियमित टैक्स देते हैं, फिर भी पैसा नहीं देने पर क्रशर बंद कराने की धमकी दी जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके क्रशर को बंद कराने के लिए आदिवासी लोगों को आगे करके हंगामा कराया जा रहा है, उनका आरोप है कि विधायक लगातार उनकी छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं और सार्वजनिक रूप से उन्हें बदनाम किया जा रहा है।

अंजनी सिंह ने आरोप लगाते हुए बताया कि 'मेरा चरित्र हनन किया जा रहा है। गढ़वा विधायक मुझे 'रंगदार' कहते हैं, जबकि मेरे खिलाफ 'रंगदारी' का एक भी मामला दर्ज नहीं है। मैं एक व्यवसायी हूं लेकिन विधायक के रवैये से परेशान हूं। उन्होंने यह भी दावा किया कि जब वे सड़क निर्माण का कार्य करा रहे थे, उस दौरान विधायक प्रतिनिधि रिंकू तिवारी द्वारा उनसे पैसों की मांग की गई थी और पैसे नहीं देने के कारण अब उनके क्रशर को बंद कराने की कोशिश की जा रही है। पत्रकार वार्ता में अंजनी सिंह ने कहा कि यदि विधायक सत्येन्द्रनाथ तिवारी एक सप्ताह के भीतर सार्वजनिक रूप से उनसे माफी नहीं मांगते हैं, तो वे उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में न्यायालय में लिखित शिकायत भी की जाएगी। अंजनी सिंह ने कहा कि वह कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से अपने सम्मान की रक्षा करेंगे और न्यायालय से उचित कार्रवाई की मांग करेंगे।

संक्षिप्त समाचार

रांची निदेशालय में श्रेत्रीय लिपिक संवर्ग नियमावली सुधार को लेकर बैठक

रांची, एजेंसी। झारखंड स्वास्थ्य लिपिकीय संघ के राज्य सचिव मनोज कुमार द्वारा निदेशालय, रांची में स्वास्थ्य विभाग के लिपिकीय संवर्ग के साथ संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें झारखंड अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के राज्य महामंत्री बीरेंद्र कुमार यादव, झारखंड चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री शैलेन्द्र तिवारी, अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शर्मीला ठाकुर और चतुर्थ वर्गीय स्वास्थ्य विभाग के संघर्ष मंत्री संत कुमार झा के नेतृत्व में क्षेत्रीय लिपिक संवर्ग नियमावली में सुधार के संबंध में विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। बैठक के दौरान निदेशालय में अपर सचिव एवं अन्य कर्मियों से लिपिकीय संवर्ग से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर वार्ता की गई। प्रतिनिधिमंडल ने नियमावली से संबंधित विषयों पर अपने विचार रखे तथा संगठनात्मक स्तर पर समन्वय और संवाद को आगे बढ़ाने पर बल दिया। इस अवसर पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने लिपिकीय संवर्ग के हितों से जुड़े मुद्दों पर एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता पर अपने विचार व्यक्त किए। बैठक में संगठन को और अधिक सशक्त एवं सक्रिय बनाने पर विशेष चर्चा हुई। संगठन की मजबूती, आपसी समन्वय तथा कर्मचारियों के बीच एकता बनाए रखने पर जोर दिया। बैठक में शम्भू सिंह (लिपिक), प्रदीप सेन, रमेश कुमार, भूपेश कुमार, संतोष कुमार गुप्ता, अजय कुमार सहित अन्य उपस्थित रहे। सभी ने संगठनात्मक गतिविधियों को मजबूती प्रदान करने और कर्मचारियों के साझा हितों के लिए निरंतर प्रयासरत रहने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

लाइट, कैमरा, एक्शन! अब खुद अपनी कहानी कह रहा झारखंड

रांची, एजेंसी। झारखंड की अपनी सिनेमाई भाषा का महत्वपूर्ण विस्तार उसके आदिवासी और जनजातीय सिनेमा में दिखाई देता है। अब सवाल सिर्फ यह नहीं रह गया है कि झारखंड को कौन फिल्मा रहा है बल्कि यह है कि झारखंड अपनी भाषाओं में खुद को किस तरह पर्दे पर प्रस्तुत कर रहा है। इस कड़ी में कई महत्वपूर्ण नाम सामने आते हैं, जिनमें कुछ प्रमुख फिल्मकारों का उल्लेख यहां किया जा रहा है। रांची के विनोद कुमार उन शुरुआती फिल्मकारों में शामिल हैं, जिन्होंने स्थानीय आदिवासी समाज और संस्कृति को केंद्र में रखकर झारखंड में फीचर फिल्म बनाने का साहस किया। उनकी फिल्म 'अक्रांत' (1988) इस दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। दूरदर्शन पर प्रसारण और मुंबई के पैनोरमा में शामिल होने से फिल्म को व्यापक पहचान मिली। युवा निर्देशक निरंजन कुजूर की फिल्म 'दुई जागर' वर्ष 2024 में बुसान अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के न्यू करंट्स खंड के लिए चयनित हुई। वर्ष 2025 के मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल में भारतीय प्रीमियर हुआ। संताली फिल्मकार रवि राज मुर्मू ने संताली भाषा में फिल्म निर्माण को नयी पहचान दिलाई और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हासिल किया। रांची से निकले नीरज शुक्ला ने शाहरुख खान अभिनीत फिल्म 'रईस' जैसी फिल्म की पटकथा लिखी। रांची के ही अभिनेता राजेश जैश भी फिल्म जगत में पहचान बना चुके हैं। सतीश मुंडा का नाम भी महत्वपूर्ण है। इनकी डिप्लोमा फिल्म 'दंश' को कई पुरस्कार मिले। डॉक्यूमेंट्री 'दृष्टि' के बाद यूरेनियम खनन जैसे अनदेखे विषय पर बनी फिल्म 'जादूगोड़ा' ने उन्हें अलग पहचान दिलाई। वर्ष 2022 में राहुल भट और प्रिया बापट अभिनीत उनकी पहली फीचर फिल्म 'चक्की' रिलीज हुई।

कमरे में बहस और छत पर गया पार्टनर, पीछे से युवती ने लगा ली फांसी

रांची, एजेंसी। राजधानी रांची के खेलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवाजी नगर से एक बेहद दुखद मामला सामने आया है। बुधवार दोपहर करीब 1:30 बजे 19 वर्षीय एक युवती ने कमरे में पंखे के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका मूल रूप से हजारीबाग जिले के इचाक की रहने वाली थी और रांची के बूटी मोड़ स्थित एक निजी कंपनी में काम करती थी। पुलिस से मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, युवती पिछले करीब एक वर्ष से शिवाजी नगर स्थित एक किराए के मकान में अपने एक युवक के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी। बताया जा रहा है कि बुधवार की दोपहर किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। विवाद बढ़ने के बाद युवक घर की छत पर चला गया, जबकि युवती कमरे के अंदर ही रही। कुछ देर बाद जब युवक छत से नीचे लौटा तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। काफी देर तक आवाज देने और दरवाजा खोलने की कोशिश के बावजूद जब अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो युवक ने आसपास के लोगों की मदद से दरवाजा तोड़ा। अंदर युवती पंखे के सहारे फंदे से लटकी मिली। युवक तुरंत उसे आनन-फानन में राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही खेलगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी।

रिम्स ने स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में रचा नया इतिहास

रांची, एजेंसी। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची में आज स्वास्थ्य सेवाओं एवं चिकित्सा शिक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत हुई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एके सिंह ने बुधवार रिम्स में अत्याधुनिक डिजिटल मेमोग्राफी, सेंट्रल लेबोरेट्री,बीएसएनएल-प्रबंधित वाई-फाई एवं सीसीटीवी कमांड कंट्रोल रूम, ओरल एवं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी ऑपरेशन थिएटर, ई-सुश्रुत एचएमआईएस झारखंड एवं ऑनलाइन मरीज अपॉइंटमेंट प्रणाली का शुभारंभ किया। इसके साथ ही नव-नियुक्त फैकल्टी सदस्यों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए।

रिम्स में खाली पड़े पदों पर नियुक्तियां होंगी : रिम्स के नए अकादमिक भवन में कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए झारखंड सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ। इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य सरकार रिम्स को देश के अग्रणी चिकित्सा संस्थानों की श्रेणी में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है, उन्होंने नव-नियुक्त शिक्षकों एवं अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी ऊर्जा और विशेषज्ञता से चिकित्सा शिक्षा एवं मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही रिम्स में खाली पड़े 94 सहायक प्राध्यापकों के पदों पर नई नियुक्तियों के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा ताकि जारी रिम्स की शैक्षणिक एवं चिकित्सीय क्षमता और सुदृढ़ हो सके।

इस मौके पर रिम्स शासी परिषद के सदस्य और कांके विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेश बैठा ने कहा कि रिम्स ने राज्य के लोगों का विश्वास अर्जित किया है और आज यह झारखंड की पहचान बन चुका है, उन्होंने कहा कि रिम्स की बढ़ती उपलब्धियों और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए रिम्स -2 की स्थापना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि 'जब रिम्स एक सिद्ध एवं सफल चिकित्सा संस्थान के रूप में स्थापित हो चुका है, तब उसी उत्कृष्टता को आगे बढ़ाते हुए रिम्स -2 का निर्माण राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम होगा'।हेल्थ डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अजय कुमार सिंह ने कहा कि राज्य सरकार रिम्स में ह्यूमन रिसोर्स, डिजिटल हेल्थ सर्विस, मॉडर्न मेडिकल इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नई नियुक्तियां, डिजिटल हेल्थ सिस्टम और प्रपोज्ड रिम्स -2 प्रोजेक्ट झारखंड के हेल्थ सिस्टम को नेशनल लेवल पर नई पहचान दिलाने में अहम रोल निभाएंगे।

रिम्स के निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी प्रो। (डॉ।) डीके सिन्हा ने सभी नव-नियुक्त शिक्षकों एवं अधिकारियों का स्वागत करते हुए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि रिम्स निरंतर उत्कृष्ट चिकित्सा शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शोध तथा सर्वोत्तम रोगी सेवाओं के लिए कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि 250 एमबीबीएस सीटों की स्वीकृति, आधुनिक स्वास्थ्य एवं डिजिटल सुविधाओं का विस्तार, नई फैकल्टी की नियुक्तियां तथा आगामी 94 सहायक प्राध्यापकों की भर्ती संस्थान के विकास की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य सरकार के सहयोग से रिम्स राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट चिकित्सा संस्थानों में अपनी सशक्त पहचान स्थापित करेगा।

कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों ने नव-नियुक्त शिक्षकों एवं अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए अपेक्षा व्यक्त की कि वे चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान एवं रोगी सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देकर रिम्स को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। साथ ही यह विश्वास भी व्यक्त किया गया कि प्रस्तावित रिम्स -2 झारखंड के लोगों को और अधिक सुलभ, उन्नत एवं विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक दूरदर्शी पहल सिद्ध होगा।

200 रुपये घूस लेने का आरोप नहीं हुआ साबित, 39 साल बाद हाईकोर्ट ने किया बरी

रांची, एजेंसी। 39 साल पुराने 200 रुपये रिश्वत लेने के मामले में सजायाफ्ता धनबाद के बसंतीमाता कोलियरी के कर्मचारी भोलू मंडल को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाइकोर्ट के जस्टिस अरुण कुमार राय की अदालत ने भोलू मंडल की अपील याचिका पर फैसला सुनाते हुए उसे मामले से बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष रिश्वत मांगने का आरोप साबित नहीं कर सका। अदालत ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में रिश्वत की मांग सिद्ध होना अनिवार्य है। केवल रिश्वत की राशि की बरामदगी या स्वीकार करना दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे में वर्ष 2002 में धनबाद सीबीआइ की विशेष अदालत द्वारा सुनायी गयी दोषसिद्धि, दो साल की सजा तथा 300 रुपये जुर्माने के आदेश को निरस्त किया जाता है। अपील की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता सुखलाल दास की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गयी थी। इसलिए उनका बयान दर्ज नहीं हो सका। वहीं सीबीआइ का एक स्वतंत्र गवाह अपने पहले बयान से मुकर गया। अदालत ने यह भी कहा कि स्वतंत्र गवाहों व सीबीआइ अधिकारियों के बयानों में रिश्वत मांगने की घटना को लेकर कई महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में केवल रिश्वत की बरामदगी पर्याप्त नहीं होती, बल्कि रिश्वत मांगने का आरोप भी संदेह से परे साबित होना जरूरी है।

धनबाद के विकास पर सियासी धरना, नए उद्योग और वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्रों पर जोर

धनबाद, एजेंसी। जिले में समग्र विकास को लेकर शहर में महाधरना आयोजित किया गया। निरसा विधायक अरूप चटर्जी और कई सामाजिक संगठनों के आह्वान पर आयोजित इस कार्यक्रम में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय, सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो, धनबाद मेयर संजीव सिंह समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। धरने के दौरान नई रेल सेवाएं, एयरपोर्ट, एम्स की तर्ज पर सुपरस्पेशलिटी अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर और औद्योगिक विकास जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया।

जमशेदपुर विधायक सरयू राय ने कहा कि धनबाद पिछले 150-200 सालों में कई विकास के अवसर गंवा चुका है और अब उन खोए हुए अवसरों की भरपाई का समय है। उन्होंने कहा कि पहले कोयला ही ऊर्जा का प्रमुख स्रोत था लेकिन अब ऊर्जा के कई नए विकल्प सामने आ चुके हैं। ऐसे में धनबाद को कोयला आधारित अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर नए उद्योगों और वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्रों को भी अपनाना होगा। उन्होंने कोलकाता बंदरगाह के बेहतर उपयोग और पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर देते हुए कहा कि इससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी।

मेयर संजीव सिंह ने कहा कि किसी भी शहर का विकास बिना ठोस योजना के संभव नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि बीसीसीएल, रेलवे, जिला प्रशासन और सभी जनप्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक बुलाकर धनबाद के विकास का रोडमैप तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि, जो नीतियां जिले के विकास में बाधा बन रही हैं, उन्हें बदलने की दिशा में सामूहिक पहल होनी चाहिए।

वहीं निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि सात विधायकों ने कार्यक्रम में आने की सहमति दी थी लेकिन कुछ जनप्रतिनिधि पूर्व निर्धारित व्यस्तताओं के कारण शामिल नहीं हो सके हैं। बीजेपी विधायक और सांसदों की अनुपस्थिति पर उन्होंने कहा कि आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं है।

रिम्स शासी परिषद की बैठक: 200 नए वेंटिलेटर, स्मार्ट कलासरूम और रोबोटिक सर्जरी को मिली हरी झंडी

रांची, एजेंसी। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी रिम्स की शासी परिषद की महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को हुई। स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गये। इस विधायक सुरेश बैठा, अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह, रिम्स के निदेशक डॉ। दीपेंद्र कुमार सिन्हा, वित्त विभाग के प्रधान सचिव, अपर सचिव शशि प्रकाश सिंह, अपर निदेशक डॉ। बाघमारे कृष्ण प्रसाद सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

इस बैठक में कुल 19 एजेंडों एवं 5 अतिरिक्त महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान रिम्स को अत्याधुनिक, मरीज-केंद्रित और विश्वस्तरीय संस्थान बनाने की दिशा में कई बड़े एवं ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। स्वास्थ्य मंत्री डॉ। इरफान अंसारी ने कहा कि अब रिम्स केवल इलाज का केंद्र नहीं, बल्कि उत्कृष्ट चिकित्सा, आधुनिक तकनीक और गुणवत्तापूर्ण मेडिकल शिक्षा का राष्ट्रीय मॉडल बनेगा। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से सभी निर्णयों को धरातल पर उतारने के सख्त निर्देश दिए।

रिम्स शासी परिषद की बैठक में रिम्स के सभी यूजी एवं पीजी छात्रावासों को पीपीपी मॉडल पर संचालित करने की दिशा में प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा पूरे रिम्स परिसर के सभी शौचालयों को एयरपोर्ट की तर्ज पर आधुनिक, स्वच्छ और अत्याधुनिक बनाने का निर्देश। एक माह के भीतर कायाकल्प सुनिश्चित करने को कहा गया।

शासी परिषद ने रिम्स अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार को हाईटेक और आकर्षक स्वरूप देने का जहां निर्णय लिया। वहीं ऑर्थोपेडिक वार्ड का पूर्ण पुनर्निर्माण कराने पर भी सहमति बनी। पुराने और जर्जर ढांचे को हटाकर आधुनिक सुविधाओं से युक्त नया वार्ड भी बनाया जाएगा। एमबीबीएस सीटें 250 होने के बाद आवश्यक भवन, छात्रावास एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं के विस्तार के लिए तकनीकी आकलन कराने का निर्देश दिया गया है।

रिम्स की जरूरत के अनुसार सभी आवश्यक चिकित्सा उपकरणों एवं मशीनों की शीघ्र खरीद सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। रिम्स शासी परिषद ने 200 अत्याधुनिक वेंटिलेटर खरीदने की सहमति दे दी है। वहीं जिन मशीनों के टेंडर पूरे हो चुके हैं लेकिन खरीद आदेश लंबित हैं, उन्हें तत्काल जारी करने का निर्देश दिया गया है। रिम्स में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्णय लेते हुए शासी परिषद ने मेडिकल शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने का निर्णय लिया है।

रांची में जल्द खुलेगा पूर्वी भारत का पहला सरकारी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग संस्थान

रांची, एजेंसी। रांची में पूर्वी भारत का पहला एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग (एएमई) और एयर होस्टेस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोनों कोर्सों का औपचारिक शुभारंभ नवंबर में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर करेंगे। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग (एएमई) पाठ्यक्रम के संचालन के लिए झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट ने दिल्ली की संस्था मेसर्स वेन्योर के साथ एमओयू किया है। वहीं, एयर होस्टेस प्रशिक्षण के लिए एआईएसईसीटी लिमिटेड, भोपाल के साथ करार किया गया है।

इन पाठ्यक्रमों का संचालन धनबाद स्थित झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट के आधारभूत ढांचे पर पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत किया जाएगा। इन पाठ्यक्रमों के शुरू होने से झारखंड के साथ-साथ बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ सहित पड़ोसी राज्यों के युवाओं को विमानन क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दूर-दराज के राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। इससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एएमई पाठ्यक्रम में 60 सीटें निर्धारित की गई हैं। यह तीन वर्षीय कोर्स होगा, जिसकी कुल फीस 6 लाख रुपये होगी। शुल्क का भुगतान तीन वार्षिक किस्तों में 2-2 लाख रुपये के रूप में किया जाएगा। एयर होस्टेस प्रशिक्षण के तहत छह माह और 12 माह अवधि के दो पाठ्यक्रम संचालित होंगे। दोनों पाठ्यक्रम में 60-60 सीटें उपलब्ध रहेंगी। छह माह के कोर्स की फीस 1,00,500 रुपये और 12 माह के डिप्लोमा कोर्स की फीस 1,55,500 रुपये निर्धारित की गई है। इस शुल्क में ड्रेस, ग्रूमिंग किट और स्विमिंग प्रशिक्षण भी शामिल रहेगा।

कोर्स का संचालन नागर विमानन महानिदेशालय की अनुमति मिलने के बाद शुरू किया जाएगा।एयर होस्टेस प्रशिक्षण के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 जुलाई निर्धारित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट के प्रबंध निदेशक कैप्टन एसपी सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर विमानन क्षेत्र में राज्य के युवाओं को नए अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग और एयर होस्टेस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम झारखंड के लिए मील का पत्थर साबित होगा और देश में विमानन क्षेत्र के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

अनियंत्रित वाहन सड़क छोड़कर घर में घुसा, 2 की मौत, कई अन्य घायल

लातेहार, एजेंसी। चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत दामोदर गांव में बुधवार की शाम तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर एक घर में घुस गई। इस दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में स्कॉर्पियो चालक अरविंद कुमार (अरविंद सिंह) और घर के बाहर बैठी महिला राखी देवी शामिल हैं।

चंदवा से बालूमाथ की ओर जा रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो दामोदर गांव के पास अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे स्थित एक घर में जा घुसी। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो का ड्राइवर समेत उस पर सवार अन्य लोग तथा घर में उपस्थित महिलाएं और बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए।

स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत पुलिस को सूचना दी और सभी घायलों को चंदवा अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने जांच के बाद अरविंद सिंह और राखी देवी को मृत घोषित कर दिया। चार घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है, जबकि शेष तीन घायलों का इलाज चंदवा अस्पताल में ही चल रहा है।

चंदवा थाना प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि घटना में दो लोगों की मौत हो गई है। मामले की पूरी जांच की जा रही है। मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लातेहार भेजा जा रहा है।

बुधवार की सुबह भी लातेहार में एक अन्य दुर्घटना हुई थी। खेत जुताई के दौरान ट्रैक्टर पलटने से ट्रैक्टर चालक राजू उरांव की मौत हो गई। लातेहार सदर थाना प्रभारी प्रमोद कुमार ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेजा और मामले की छानबीन शुरू कर दी। लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं से लोगों की जान जा रही है, लेकिन अभी भी कई लोग सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।

रांची में डूरंड कप को लेकर जोश, पहले दिन 12 हजार से ज्यादा 'जीरो टिकट' बांटे गए

रांची, एजेंसी। 135वें डूरंड कप-2026 के आगाज से पहले राजधानी रांची में फुटबॉल का जुनून सिर चढ़ कर बोलने लगा है। बुधवार से 'जीरो टिकट' का वितरण शुरू हो गया। पहले दिन 12256 टिकट जारी किये गये। आयोजन समिति की ओर से बताया गया कि पहले मैच के लिए कुल 25000 टिकट हैं। बाकी बचे टिकट 23 जुलाई को जारी किये जायेंगे। इसके बाद भी यदि टिकट शेष रहते हैं, तो 25 और 26 जुलाई को वितरित किये जायेंगे। टिकट 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर बांटे जा रहे हैं। इसके लिए स्टेडियम परिसर में कुल 12 काउंटर बनाये गये हैं। इनमें गेट संख्या 11 से 13 के बीच 10 काउंटर तथा गेट संख्या 23 के पास दो अतिरिक्त काउंटर संचालित किये जा रहे हैं। बुधवार को टिकट लेने पहुंचे फुटबॉल प्रेमियों में डूरंड कप को लेकर खासा उत्साह दिखा। लोगों का कहना है कि निःशुल्क टिकट मिलने से अधिक से अधिक दर्शकों को स्टेडियम में विश्वस्तरीय फुटबॉल देखने का अवसर मिलेगा। कई काउंटर होने के कारण भीड़ के बावजूद लोगों को टिकट लेने में कोई परेशानी नहीं हुई। फुटबॉल प्रेमियों का मानना है कि झारखंड में फुटबॉल के प्रति भी लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है और डूरंड कप की मेजबानी राज्य के लिए गर्व की बात है। खेल निदेशक छवि रंजन ने बताया कि डूरंड कप के सफल आयोजन को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं। सुरक्षा, पार्किंग, टिकट वितरण, चिकित्सा सुविधा और दर्शकों की अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है।

कांग्रेस की मुहिम 'छात्रों की गूंज'

रांची के नवीन सरना कॉलेज हॉस्टल पहुंचकर मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने छात्रों से किया संवाद

रांची, एजेंसी। पेपर लीक, शिक्षा नीति और छात्रों के कई मुद्दों को केंद्र में रखकर कांग्रेस की ओर से लगातार 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। इस मुहिम के तहत रांची के हरमू स्थित नवीन सरना कॉलेज छात्रावास में ' विद्यार्थी संवाद ' का आयोजन किया गया। इस संवाद कार्यक्रम को राज्य की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने संबोधित किया।

इस मौके पर मंत्री ने कहा कि आज देश के युवाओं का भविष्य पेपर लीक के जंजाल में फंस कर तबाह हो रहा है और राज सिंहासन पर बैठी तानाशाही नरेंद्र मोदी सरकार बेपरवाह होकर चैन की नींद सो रही है। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि इतिहास गवाह है कि जब हिटलर की तानाशाही नहीं चली तो नरेंद्र मोदी की तानाशाही हिंदुस्तान की जनता कैसे बर्दाश्त करेगी

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि कांग्रेस संवैधानिक तरीके से युवाओं की लड़ाई जीतने के साथ उनका हक दिलाने का काम करेगी। नवीन सरना कॉलेज छात्रावास के छात्रों के साथ संवाद के दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर छात्रों की तैयारी और कम संसाधन में शिक्षा ग्रहण करने की तमाम चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा हुई ।

ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि आज केंद्र में छात्रों के मुद्दे पर असंवेदनशील सरकार बैठी हुई है, जिसका नाता ना तो देश के युवाओं से है और ना उनके रोजगार से है। देश के युवा महंगी होती शिक्षा व्यवस्था में जब दिन-रात मेहनत करने के बाद प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होते हैं, तब उन्हें नियुक्ति पत्र मिलने से पहले पेपर लीक का समाचार प्राप्त होता है।

उन्होंने कहा कि साल 2016 से अब तक पेपर लीक के 152 मामले सामने आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े बताने के लिए काफी है कि देश के भविष्य के साथ केंद्र सरकार खेल रही है। आज काबिलियत के दम पर नहीं, बल्कि पेपर लीक के दम नौकरी बांटने की शुरुआत केंद्र सरकार ने की है। उन्होंने कहा कि देश के भविष्य की लड़ाई में कांग्रेस युवाओं के साथ खड़ी है।

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि राहुल गांधी डरने वाले नेता नहीं हैं। संसद में उन्हें बोलने से रोका जाता है , उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं, नेता प्रतिपक्ष होने का हक उन्हें सदन में नहीं मिलता इसके बावजूद राहुल गांधी लोकतांत्रिक तरीके से देश की जनता के सवाल और छात्र-नौजवानों के हक की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने में लगे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे सांसदों के साथ क्या हुआ ये पूरा देश जान चुका है। कांग्रेस जनता की आवाज उठाने या लाठी खाने को तैयार है, पर इस लड़ाई में सबको अपना योगदान देना होगा। फिर वो चाहे आंदोलन में शामिल हो कर या उसका समर्थन कर के। जब लगातार पेपर लीक हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई दोषी है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना ही होगा। जब तक ऐसा नहीं होता है, तब तक सड़क से संसद तक ये लड़ाई जारी रहेगी।

विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम में छात्रावास के इन्द्रनाथ उरांव और सुमित उरांव ने मौजूदा परीक्षा प्रणाली की कड़े शब्दों में निंदा की। छात्रों ने कहा कि पेपर लीक का दर्द आर्थिक-सामाजिक स्तर पर संघर्ष कर परीक्षा में शामिल होने वाले युवाओं से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आज पेपर लीक की लंबी फेहरिस्त होने के बावजूद केंद्रीय शिक्षा मंत्री बेशर्मी के साथ बयानबाजी कर रहे हैं।

संक्षिप्त समाचार

नालंदा में बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 25 जुलाई को लगेगा जॉब कैंप

नालन्दा, एजेंसी। युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग और जिला नियोजनालय, बिहार शरीफ (नालंदा) के संयुक्त देखरेख में इच्छुक बेरोजगार युवाओं के लिए एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह रोजगार मेला आने वाले 25 जुलाई को आयोजित किया जाएगा, जिसका समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया है। यह पूरा आयोजन संयुक्त श्रम भवन, जिला नियोजनालय, बिहार शरीफ (नालंदा) के परिसर में संपन्न होगा। इस मेले में आठवीं, दसवीं, बारहवीं कक्षा पास के साथ-साथ स्नातक, स्नातकोत्तर, आईटीआई, डिप्लोमा और एमबीए जैसी शैक्षणिक योग्यता रखने वाले युवा भाग ले सकते हैं। रोजगार मेले में भाग लेने वाले प्रमुख नियोजकों के रूप में रीशव ऑटो मोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, एल एंड टी कंस्ट्रक्शन स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, क्वेस्स कॉर्प लिमिटेड, शांतमणि पेपर मिल्स (बिहारशरीफ), प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन और फ्रीडम एम्प्लॉयबिलिटी अकादमी जैसी प्रतिष्ठित कंपनियां पहुंच रही हैं। मेले में हिस्सा लेने वाले युवाओं को अपने साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे एनसीएस निबंधन, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की कॉपी और बायोडाटा (रिज्यूम) लाना अनिवार्य होगा, जिसमें एनसीएस निबंधन का काम कार्यालय में ही किया जा रहा है। इसके अलावा जिला नियोजनालय की ओर से युवाओं के लिए अन्य योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जिनमें स्टडी किट योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त किताबें दी जाती हैं। टूल किट योजना के तहत प्रमाणित संस्था से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को मुफ्त टूल किट प्रदान किया जाता है। इन योजनाओं का फायदा उठाने के लिए एनसीएस पोर्टल पर 6 माह पुराना निबंधन और वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। इन योजनाओं और मेले से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जिला नियोजनालय बिहारशरीफ से संपर्क किया जा सकता है, जिसका संपर्क सूत्र 06112-359276 है।

मधुबनी में सकरी के पूर्व मुखिया 10 साल की सजा:2018 के जानलेवा हमले मामले में कोर्ट ने दिया फैसला

मधुबनी, एजेंसी। मधुबनी जिले के सकरी थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 में हुए जानलेवा हमले के मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार पांडेय की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया। अदालत ने सकरी के पूर्व मुखिया अली अहमद उर्फ मुन्ना बॉस को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना, धारा 341 के तहत एक माह का कारावास, धारा 325 के तहत पांच वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये का जुर्माना तथा धारा 504 के तहत दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत तीन वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये का जुर्माना तथा धारा 30 के तहत छह माह का कारावास और दो हजार रुपये का जुर्माना सुनाया गया। अदालत ने सभी सजाएं साथ-साथ चलाने का आदेश दिया। सजा निर्धारण के दौरान लोक अभियोजक शिव शंकर प्रसाद राय ने आरोपी के गंभीर अपराध का हवाला देते हुए कठोर सजा की मांग की। वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता शिव कुमार ठाकुर ने आरोपी के लिए न्यूनतम सजा देने का अनुरोध किया। लोक अभियोजक के अनुसार, 17 सितंबर 2018 को उमर महमूद को सूचना मिली कि उनके पुत्र का अपहरण किया जा रहा है। सूचना मिलने पर जब वे घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा कि आरोपी अली अहमद उर्फ मुन्ना बॉस अपने सहयोगियों के साथ उनके पुत्र को जबरन वाहन में बैठाने का प्रयास कर रहा था। आरोप है कि उमर महमूद के पहुंचते ही आरोपी ने पिस्तौल से जान से मारने की नीयत से गोली चला दी, जो उनकी बांह में लगी। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी अपने साथियों के साथ फरार हो गया। इस मामले में सकरी थाना में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की थी।

पोस्टिंग और ट्रांसफर के नाम पर 25 लाख की ठगी

आरोपी के मोबाइल में मिले आईएएस-आईपीएस अधिकारियों के नंबर

मोतिहारी, एजेंसी। पूर्वी चंपारण जिले में पोस्टिंग और ट्रांसफर के नाम पर लाखों रुपये की ठगी करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। राजन जायसवाल पर आरोप है कि वह खुद को प्रभावशाली और ऊंचे संपर्क वाला व्यक्ति बताकर एसडीएम सहित अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर पोस्टिंग कराने का दावा करता था। इसके बदले में 25 लाख रुपये की मांग कर रहा था।

ट्रांसफर-पोस्टिंग के नाम पर गोरखधंधा: मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई, जब पुलिस ने आरोपी के मोबाइल फोन की जांच की। शुरुआती जांच में मोबाइल से कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के व्यक्तिगत मोबाइल नंबर मिलने की जानकारी सामने आई है। इसके अलावे पोस्टिंग, ट्रांसफर और टेंडर से जुड़े कई लोगों के संपर्क भी मोबाइल में सेव पाए गए हैं। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी के पास ये नंबर कैसे पहुंचे और कहीं इसके पीछे कोई संगठित गिरोह तो सक्रिय नहीं है?

शिकायत के बाद पुलिस ने की कार्रवाई: पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ शिकायत मिली थी कि वह सरकारी अधिकारियों की पोस्टिंग कराने के नाम पर बड़ी रकम की मांग कर रहा है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। शुरुआती पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं, जिसके आधार पर जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है।

पुलिस यह भी पता लगा रही है कि आरोपी अब तक कितने लोगों से संपर्क कर चुका था और किन-किन व्यक्तियों से पोस्टिंग के नाम पर पैसे की मांग की गई थी। अगर जांच में और पीड़ित सामने आते हैं तो उनके बयान भी दर्ज किए जाएंगे।

मोबाइल की जांच में मिले कई अहम सुराग: राजन जायसवाल के मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण संपर्क नंबर मिले हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार मोबाइल में बिहार के विभिन्न जिलों में पदस्थापित कई आईएएस अधिकारियों के व्यक्तिगत नंबर, आईपीएस अधिकारियों के संपर्क और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई अन्य लोगों के नंबर मौजूद हैं।

इसके अलावे पोस्टिंग, ट्रांसफर, ठेकेदारी और टेंडर से जुड़े कुछ व्यक्तियों के संपर्क भी मिले हैं। हालांकि केवल किसी अधिकारी या व्यक्ति का मोबाइल नंबर किसी फोन में सेव होना अपने आप में किसी की संलिप्तता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। पुलिस इस पहलू की भी गहन जांच कर रही है कि इन नंबरों का उपयोग किस उद्देश्य से किया गया और आरोपी की उनसे वास्तविक बातचीत या संबंध था या नहीं?

कॉल डिटेल और व्हाट्सएप चैट की जांच: मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में साइबर सेल को भी शामिल किया गया है। पुलिस आरोपी के मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर), व्हाट्सएप चैट, मैसेज, कॉल हिस्ट्री और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है।

जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आरोपी ने किन लोगों से बातचीत की, किसे पोस्टिंग का भरोसा दिया और क्या किसी व्यक्ति से पैसे भी लिए गए? यदि डिजिटल साक्ष्यों से किसी बड़े नेटवर्क के संकेत मिलते हैं तो जांच का दायरा और बढ़ाया जा सकता है।

अधिकारियों को किया गया अलर्ट : पुलिस ने मोबाइल में मिले संपर्क नंबरों की सूची तैयार कर संबंधित अधिकारियों को भी सतर्क किया है। जांच एजेंसियां यह सुनिश्चित करना चाहती हैं कि कहीं किसी अधिकारी का नाम या पहचान का दुरुपयोग करके लोगों को ठगा तो नहीं गया?

पुलिस यह भी जांच रही है कि आरोपी सिर्फ अधिकारियों के नाम का इस्तेमाल कर लोगों को झांसा देता था या फिर उसके किसी स्तर पर वास्तविक संपर्क भी थे। फिलहाल इस संबंध में जांच जारी है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।

क्या बोले एसपी?: मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस सभी डिजिटल और तकनीकी साक्ष्यों की जांच कर रही है। साथ ही पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। एसपी ने कहा कि कोई भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे।

लोगों से सतर्क रहने की अपील: पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि सरकारी नौकरी, पोस्टिंग, ट्रांसफर या किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्ति कराने के नाम पर पैसे मांगने वाले किसी भी व्यक्ति के झांसे में न आएं। सरकारी पदस्थापन और तबादले की अपनी निर्धारित प्रशासनिक प्रक्रिया होती है और इन्हें पैसे लेकर प्रभावित करने का दावा करने वाले लोगों से सावधान रहना चाहिए।

यदि कोई व्यक्ति पोस्टिंग या ट्रांसफर के नाम पर रुपये मांगता है या खुद को प्रभावशाली बताकर सरकारी काम कराने का दावा करता है, तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। आपात स्थिति में 112 नंबर पर कॉल करें या अपने नजदीकी थाने में शिकायत दर्ज कराएं।

बिहार में पूर्व विधायक के मकान से 158 किलो गांजा जब्त, केयरटेकर गिरफ्तार

अररिया, एजेंसी। बिहार की अररिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नगर थाना क्षेत्र स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क के पास स्थित एक मकान से भारी मात्रा में गांजा जब्त किया गया है। ये मकान पूर्व भाजपा विधायक जयप्रकाश यादव का है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। पूर्व विधायक के मकान से गांजा जब्तः पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नरपतगंज के पूर्व भाजपा विधायक जयप्रकाश यादव के कामत से 158 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। मामले में केयरटेकर अवधेश ऋषिदेव को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि मुख्य तस्कर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।

सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) सुशील कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना पुलिस ने कामत में छापेमारी की। तलाशी के दौरान वहां से 158 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस जांच में सामने आया है कि गांजे की खेप को कामत में स्टोर कर रखा गया था और अगले दिन इसकी तस्करी की जानी थी।

केयरटेकर गिरफ्तारः पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अवधेश ऋषिदेव कामत की देखरेख करता था और वहीं रह रहा था। पूछताछ के आधार पर पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

एसडीपीओ सुशील कुमार ने बताया कि इस अवैध कारोबार में शामिल मुख्य तस्कर और अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि बरामद गांजा कहां से लाया गया था और इसकी आपूर्ति किन स्थानों पर की जानी थी।

प्रशांत किशोर के नेताओं को तंग कर रही पुलिस?, जनसुराज ने चुनाव आयोग से की शिकायत

पटना, एजेंसी। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के बीच प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी ने बुधवार को प्रशासन और पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) से शिकायत की।

जनसुराज ने की प्रशासन की ईसी से शिकायत: प्रशांत किशोर की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात की। पार्टी ने आचार संहिता के उल्लंघन और पार्टी कार्यकर्ताओं को कथित रूप से परेशान किए जाने का आरोप लगाया।

क्या बोले मनोज भारती?: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात के बाद मनोज भारती ने कहा कि सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन द्वारा कथित रूप से किए जा रहे आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में दस्तावेज और साक्ष्य सौंपे हैं।

कार्यकर्ताओं को परेशान करने का आरोप: उन्होंने आरोप लगाया कि पटना समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में जन सुराज के कार्यकर्ताओं को बिना किसी एफआईआर और वैधानिक आधार के पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है।

कार्यकर्ताओं को थाने में बैठाकर रखा गया': उन्होंने दावा किया कि पीरबहोर थाना क्षेत्र में एक कार्यकर्ता को देर रात घर लौटने के दौरान पुलिस ने परेशान किया। वहीं, 21 जुलाई को अफरोज अहमद और तौसिफ नामक दो कार्यकर्ताओं को बिना कारण थाने में बैठाकर रखा गया।

देर रात कार्यकर्ताओं के घर पहुंच रही पुलिस: उन्होंने आगे बताया कि, इसके अलावा, बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में पार्टी के प्रदेश सचिव रवि नारायण तथा सिवान में पार्टी नेता शाहनवाज आलम के घर भी देर रात पुलिस पहुंचने और पूछताछ करने का आरोप लगाया गया।

दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग: मनोज भारती ने कहा कि इन सभी मामलों की निष्पक्ष जांच कराकर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने और प्रशासन को निष्पक्ष तरीके से काम करने का निर्देश देने की मांग निर्वाचन आयोग से की गई है।

बिहार में द्वार पर दस्तक दे रही कोसी, लोगों में खौफ, सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन शुरू

सहरसा , एजेंसी। बिहार के सहरसा जिले में कोसी के जलस्तर में बढ़ोतरी के साथ नौहट्टा प्रखंड के केदली पुनर्वास वार्ड संख्या-11 में बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं। पूरे इलाके में पानी फैल जाने से जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। हालात ऐसे हैं कि बाढ़ का पानी घरों में घुस चुका है। लोगों के लिए अपने ही घरों में रहना मुश्किल हो गया है।

कोसी नदी ने दिखाया विकराल रूप : घरों में पानी भर जाने के कारण दैनिक जीवन की सभी गतिविधियां प्रभावित हो गई हैं। लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती भोजन बनाने, पीने के लिए स्वच्छ पानी जुटाने और मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था करने की है। कई परिवार जरूरी सामान के साथ घर छोड़कर ऊंचे तटबंधों और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। सबसे अधिक परेशानी छोटे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को उठानी पड़ रही है।

सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन : ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ का पानी लगातार जमा रहने से संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। जलजमाव के कारण गांव के अंदर आवागमन लगभग ठप हो गया है। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जरूरत का सामान लाना और मरीजों को अस्पताल पहुंचाना भी चुनौती बन गया है।

ग्रामीण ने सरकार से की मांग : स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल राहत सामग्री उपलब्ध कराने, नावों की व्यवस्था करने, मेडिकल टीम भेजने और स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि हर वर्ष बाढ़ आने पर उन्हें इसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है।यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति और गंभीर हो सकती है।

प्रशासन कब तक पहुंचाएगा मदद? : बाढ़ प्रभावित परिवार अब प्रशासन से त्वरित राहत और पुनर्वास की उम्मीद लगाए बैठे हैं। लोगों का कहना है कि संकट की इस घड़ी में समय पर सहायता ही उनके लिए सबसे बड़ा सहारा साबित होगी। अब निगाहें प्रशासन पर टिकी हैं कि प्रभावित इलाकों तक राहत कितनी तेजी से पहुंचती है। बाढ़ पीड़ितों को इस संकट से उबारने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जाते हैं?

नेपाल और बिहार में बारिश से मुश्किल बढ़ी : नेपाल के तराई इलाकों में हो रही बारिश और बिहार में मानसून की बारिश के कारण निचले इलाके के लोगों के लिए खतरा बढ़ गया है। कोसी हर घंटे अपना आकार बढ़ाती जा रही है। कोसी बराज पर दबाव बढ़ने से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है जिससे बाढ़ जैसे हालात बनने लगे हैं। अब देखना है कि प्रशासन कब तक डूब रहे गांवों की मदद को हाथ पहुंचाता है।

बनमा ईटहरी थाना नए भवन में जल्द होगा शिफ्ट, आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी

सहरसा, एजेंसी। सहरसा जिले के बनमा ईटहरी प्रखंड में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। वर्षों से पुराने भवन में संचालित बनमा ईटहरी थाना अब जल्द ही अपने नए और आधुनिक भवन में स्थानांतरित होगा। नए थाना भवन का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है, जबकि परिसर की सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल का निर्माण अंतिम चरण में है। इसके पूर्ण होते ही नए भवन में थाना संचालन शुरू कर दिया जाएगा।

यह नया थाना भवन आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। इसमें थाना प्रभारी कक्ष, कार्यालय, रिकॉर्ड रूम, हाजत, पूछताछ कक्ष और बैठक कक्ष सहित पुलिस कार्यों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इन सुविधाओं से पुलिसकर्मियों को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा, वहीं फरियादियों को भी अपनी शिकायत दर्ज कराने और समाधान पाने में अधिक सुविधा होगी।

पुराने भवन में सीमित जगह और संसाधनों के कारण पुलिस कार्यों के संचालन में कई व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। नए भवन में शिफ्ट होने के बाद कार्यों का निष्पादन अधिक व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से हो सकेगा। साथ ही, अभिलेखों के सुरक्षित रख-रखाव और प्रशासनिक कार्यों में भी सुधार आएगा। स्थानीय लोगों का मानना है कि आधुनिक थाना भवन के शुरू होने से क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था और मजबूत होगी। इससे पुलिस और आम जनता के बीच समन्वय बेहतर होगा, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों का भरोसा बढ़ेगा तथा विभिन्न मामलों के निष्पादन में भी तेजी आने की उम्मीद है।

भागलपुर-15 मौत के 2 दोषियों को 10-10 साल की सजा:4 साल पहले अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुआ था ब्लास्ट

भागलपुर, एजेंसी। चार साल पहले आधी रात को भागलपुर में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाकों के बाद काजवलीचक इलाका दहल गया था। ब्लास्ट की गूंज 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों समेत 15 लोगों की मौत हुई थी। घटनास्थल के पास तीन मकान मलबे में तब्दील हो गए थे। भागलपुर सिविल कोर्ट के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज-11 ज्योति कुमार कश्यप की अदालत ने तातारपुर थाना क्षेत्र के काजवलीचक बम ब्लास्ट मामले में दो दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है।

कोर्ट ने हबीबपुर के चमेलीचक के रहने वाले मोहम्मद आजाद और काजवलीचक के ही रहने वाले नवीन मंडल को दोषी करार दिया था। मामले में आरोपी आशीष कुमार गुप्ता, अशोक मंडल उर्फ गुड्डू और धनंजय मंडल को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।

जांच के दौरान पुलिस ने पाया था कि विस्फोटक सामग्री को पटाखा बनाने के उद्देश्य से अवैध रूप से रखा गया था, जिससे धमाका हुआ था। घटना के बाद तातारपुर थाने के तत्कालीन एएसआई पूर्णेंदु कुमार ने एफआईआर दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान कुल 13 गवाहों के बयान दर्ज किए गए।

काजवलीचक इलाके के लोग खाना खाकर सो चुके थे। हर ओर अंधेरा पसरा था। तभी आधी रात को 10 मिनट के अंदर ताबड़तोड़ धमाके हुए। धमाके से एक दो मंजिला मकान और तीन पक्के घर मलबे में तब्दील हो गए। धमाका इतना जोरदार था कि 3 किलोमीटर के दायरे में मलबा बिखर गया। 4 परिवार पूरी तरह से तबाह हो गए थे। धमाके में नवजात समेत एक ही परिवार के 5 लोगों समेत कुल 14 लोगों की मौत हो गई। 15वीं मौत 23 साल की आयशा की सिलीगुड़ी के अस्पताल में इलाज के दौरान हुई थी। हादसे में 10 से अधिक लोग घायल भी हुए थे, जिन्हें मायागंज अस्पताल में एडमिट कराया गया था। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के पहुंचने से पहले आसपास

के लोगों ने मकान के मलबे के नीचे दबे लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया था।

'ब्लास्ट के बाद लगा भूकंप आया है, चारों ओर सिर्फ धुआं ही धुआं था'

घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया था कि बम धमाके के बाद कुछ देर के लिए समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। धमाका इतना जोरदार था कि लगा भूकंप आया है। जिस मकान में धमाका हुआ था, वहां आधे घंटे तक सिर्फ धुआं ही दिख रहा था। सड़क पर साफ-साफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। स्टेशन चौक से लेकर उर्दू बाजार तक करीब 5 किलोमीटर के इलाके में आवाज गूंजी थी।

शीला देवी ने बताया था कि धमाके के बाद मैं तीसरी मंजिल से नीचे उतरी तो देखा कि सब कुछ खत्म हो चुका था। मेरा लाल सोनू कहां है, उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। वो गोतनी का बेटा है, उसकी मां नहीं है। मैं ही उसकी मां हूं। मैं ही उसकी देखभाल करती हूं। एक मंजिल पर बेटा रिंकू और बहू थे। अभी दोनों कहां है, कुछ मालूम नहीं। बेटी जया का भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। छोटा बेटा भी रूम में था। बीच वाला और नीचे का फ्लोर गिर गया। पति ओमप्रकाश बीमार हैं। घर में हैं। बाकी कुछ लोग अस्पताल गए हैं। पता नहीं वह लोग किस हाल में होंगे।

'नींद खुली तो लगा कि कहीं दूसरी जगह गिरा हुआ हूं' : घायल सुमित ने बताया था, 'रात में खाना खाकर सो गया था। अचानक तेज धमाके से जब नींद खुली तो लगा कि कहीं दूसरी जगह गिरा हुआ हूं। देखते ही देखते इलाके में चीख पुकार मच गई। बारूद की गंध से लगा कि धमाका हुआ है। धुएं का गुबारा जैसे-जैसे कम हुआ सड़क पर धमाके का असर दिखने लगा। सामने के मकान और शटर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके थे।'

बारूद की गंध भी आसपास के इलाके में तेजी से फैल गई : मोहम्मद शकील ने बताया था, 'धमाके के साथ बारूद की गंध भी आसपास के इलाके में तेजी से फैल गई। इसके बाद लगा कि यह बम का धमाका हुआ है। अगर धमाका रात 7 से 8 बजे या सुबह होती तो हालत और भी मुश्किल हो सकते थे।' ततारपुर के अजहर अख्तर शकील ने बताया था, 'बेड पर सोने के लिए कहा गया था कि धमाके की गूंज सुनाई दी। ऐसा लगा कि घर के बगल में किसी ने धमाका किया है। जब आसपास के लोगों को भागते देखा तो पता चला कि काजवली चक में धमाका हुआ है।'

ब्लास्ट के बाद करीब 3 किलोमीटर के एरिया में फैले मलबे को एसडीआरएफ और नगर निगम की टीम करीब 18 घंटे तक साफ करती रही थी। तत्कालीन डीआईजी सुजीत कुमार ने बताया था कि अवैध पटाखा निर्माण और स्टोरेज के कारण ब्लास्ट हुआ है।

संक्षिप्त समाचार

मानसिक तनाव में था अतुल, मां से कहा था दामिनी मुझे मरवा देगी

मेरठ, एजेंसी। चर्चित अतुल हत्याकांड की जांच में नए तथ्य सामने आ रहे हैं। संकेत मिल रहा है कि अतुल लंबे समय से मानसिक तनाव में था। उसने अपनी निजी परेशानियां परिवार या करीबी लोगों से साझा नहीं की थीं।अतुल ने परिवार की मर्जी के खिलाफ दामिनी से प्रेम विवाह किया था। इसी कारण वह वैवाहिक जीवन की दिक्कतें किसी को बता नहीं पा रहा था। अतुल को पत्नी दामिनी और उसके प्रेमी तुषार की नजदीकियों पर शक था। उसने दामिनी से इस बारे में सवाल भी किया था। दामिनी ने किसी भी संबंध से इन्कार कर दिया था। इसके बाद भी अतुल का संदेह दूर नहीं हुआ। वह भीतर-ही-भीतर घुटता रहा। अतुल ने कुछ समय पहले अपनी मां से जान को खतरा बताया था। उसने आशंका जताई थी कि दामिनी उसे मरवा सकती है। हालांकि, उस समय किसी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। दामिनी पहले भी अतुल को खाने में नशीली गोलियां देती थी। पुलिस अब इस पहलू की गहराई से पड़ताल कर रही है। वह यह जांच रही है कि क्या दामिनी को दवा की सही मात्रा का अभ्यास था। पुलिस सभी साक्ष्यों को जोड़कर इस सनसनीखेज हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी है

आरोपी पारस सोम की उम्र पर फैसला टला, पत्रावली आरक्षित

मेरठ, एजेंसी। कपसाड़ हत्याकांड के मुख्य आरोपी पारस सोम की उम्र को लेकर बुधवार को निर्णय पारित नहीं हो पाया। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट की अदालत ने समय के अभाव के चलते पत्रावली को निर्णय हेतु आरक्षित कर लिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई पर फैसला आने की उम्मीद है। आरोपी पारस सोम को जुवेनाइल बोर्ड ने पहले बालिग घोषित किया था। इस फैसले के विरुद्ध न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट की अदालत में चुनौती दी गई थी। अदालत में यह याचिका दायर की गई थी कि आरोपी को नाबालिग माना जाए। बुधवार को इस महत्वपूर्ण प्रकरण में फैसला आने की उम्मीद थी। हालांकि, समय की कमी के कारण अदालत निर्णय नहीं सुना सकी। अब पत्रावली को निर्णय के लिए नियत किया गया है। अगली सुनवाई पर इस मामले में अंतिम फैसला आने की संभावना है। यह मामला सरधना थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव से जुड़ा है। आरोपी पारस सोम पर 08 जनवरी 2026 को अनुसूचित जाति की महिला सुनीता की हत्या करने उसकी बेटी रूबी का अपहरण करने का भी आरोप है। इस संबंध में थाना सरधना में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की उम्र का निर्धारण महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

शादी में आए युवक ने पेड़ पर फंदा लगाकर दी जान

आगरा, एजेंसी। थाना लोधा क्षेत्र में गांव बाढ़ौन में एक शादी समारोह में आए युवक ने पत्नी से विवाद के बाद पेड़ पर फंदा लगाकर जान दे दी। बुधवार सुबह उसका शव पेड़ से लटका मिला। गौतमबुद्ध नगर के थाना जेवर के गांव रायपुर गांव निवासी पवन कुमार (25) पुत्र गोपाल अपनी पत्नी नीरा के साथ मंगलवार को गांव बाढ़ौन में आया था। यहां उसकी पत्नी के मामा रामचरण के बेटे पुष्पेंद्र की बुधवार को बरात जानी थी। परिवार शादी की तैयारियों में जुटा था। मंगलवार रात किसी बात को लेकर पवन और उसकी पत्नी नीरा के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद पवन घर से निकल गया। बुधवार सुबह भरतपुर की मढ़ी के पास एक नीम के पेड़ पर उसका शव उसकी ही शर्ट के फंदे से लटका मिला। खेतों की ओर जा रहे ग्रामीणों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। सीओ गभाना महेश कुमार ने बताया मामले में परिजनों ने कोई तहरीर नहीं दी है।

खैराती टोला छोड़कर बाकी जगह मिलेगा पानी, सीवर लाइन का काम जारी

आगरा, एजेंसी। आगरा में नमामि गंगे के तहत खैराती टोला पंपिंग स्टेशन पर सीवर की लाइन से क्रॉस कर रही पानी की लाइन हटाने के काम के कारण जलनिगम ने दो दिन का शटडाउन लिया था, लेकिन कैप का उपयोग करने के कारण बृहस्पतिवार को खैराती टोला छोड़कर अन्य जगहों पर जलापूर्ति सामान्य रहने का दावा किया गया है। बुधवार रात ही लाइन को चालू किया गया, लेकिन ताजगंज, खैराती टोला लाइन की जगह अन्य जगहों पर आपूर्ति की गई। जलकल महाप्रबंधक कुमार गौरव ने बताया कि दो दिन का शटडाउन जलनिगम ने लिया था लेकिन सीवर लाइन क्रॉस करने के काम में पानी की लाइन में कैप का उपयोग किया गया। अब जब वह लाइन जोड़ेंगे, तब पानी की आपूर्ति बंद की जाएगी। हालांकि पानी की लाइन को काटने पर गड्ढे में पानी भर गया। दरअसल, पाइपलाइन में इतना पानी रहता है कि गहरे गड्ढे को पूरा भर दे। डी-वाटरिंग के बाद दोपहर में काम शुरू किया गया। पानी भरने से कर्मचारी गहरे गड्ढे में काम नहीं कर पाए। जलकल महाप्रबंधक के मुताबिक बृहस्पतिवार को जलापूर्ति सामान्य रहेगी।

84% मरीजों ने छोड़ा मुरारीलाल चेस्ट अस्पताल

उर्सला अस्पताल में भी हालात खराब

कानपुर, एजेंसी। कानपुर में सरकारी अस्पतालों में पहुंच रहे मरीज अव्यवस्थाओं के दर्द से कराह कर बीच में ही इलाज छोड़कर लौट रहे हैं। शहर के प्रमुख अस्पतालों में बिना बताए जाने वाले मरीज (लामा) और मरीज के अनुरोध पर डिस्चार्ज (डीओपीआर) के बढ़ते आंकड़े स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत बयां कर रहे हैं। सबसे खराब स्थिति मुरारीलाल चेस्ट अस्पताल की है जहां जून में भर्ती हुए 450 मरीजों में से 381 बिना बताए चले गए।

यानी भर्ती मरीजों में आधे से अधिक अस्पताल की व्यवस्थाओं से परेशान होकर गायब हो गए। इस अस्पताल में जून में 58 मरीजों की मौत हुई जबकि केवल 11 मरीजों का इलाज अभी भी जारी है। सूत्रों के अनुसार मुरारीलाल अस्पताल से मरीजों के जाने का मुख्य कारण व्यवस्थाओं में कमी बताई जा रही है। अस्पताल में लिफ्ट लंबे समय से खराब है। सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं है।

डॉक्टरों के व्यवहार को लेकर भी शिकायतें सामने आ रहीं : मरीजों और उनके परिजनों के साथ स्टाफ तथा जूनियर डॉक्टरों के व्यवहार को लेकर भी शिकायतें सामने आ रही हैं। सबसे गंभीर आरोप अस्पताल में बाहर से जांचें और दवाइयां लिखने की हैं। पिछले महीने दो कर्मचारी भी पकड़े गए थे जो मरीजों के सैंपल लेकर निजी लैब जांच के लिए जा रहे थे। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए एक कर्मचारी को हटा दिया था, जबकि दूसरा शिकायत के बाद से ड्यूटी पर नहीं आया।

डीओपीआर दर्ज करने का दबाव बनाया जा रहा : मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने तुरंत परिसर में ही जांच की व्यवस्था शुरू कर दी थी। वहीं मरीजों का बिना बताए अस्पताल से निकल जाना सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल रहा है। अस्पताल में सुरक्षाकर्मी तैनात होने के बावजूद ऐसा हो रहा है। वहीं अस्पताल सूत्रों के अनुसार लामा मरीजों की बढ़ती संख्या कम दिखाने के लिए कुछ मामलों में उन्हें डीओपीआर दर्ज करने का दबाव बनाया जा रहा है। इससे वास्तविक आंकड़ों पर भी सवाल उठ रहे हैं।

हैलट इमरजेंसी से ही चले जाते काफी मरीज : जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से संबद्ध हैलट अस्पताल में जून में 6,341 मरीज भर्ती हुए। इनमें करीब 300 को इमरजेंसी से उसी दिन या अगले दिन अनुरोध पर डिस्चार्ज किया गया। मेडिसिन, बाल रोग, सर्जरी और हड्डी रोग विभागों में भी करीब 10 प्रतिशत मरीज डीओपीआर हो रहे हैं।

कई मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ा

उर्सला से 200 मरीज बिना बताए गए

उर्सला अस्पताल में जून में 2,320 मरीज भर्ती हुए। इनमें 1,360 मरीजों को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया गया। करीब 400 भर्ती हैं। 200 से अधिक मरीज बिना सूचना अस्पताल छोड़कर चले गए। वहीं करीब 345 मरीजों को रेफर किया गया। शेष मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

कांशीराम अस्पताल में भी बढ़े मामले : कांशीराम संयुक्त चिकित्सालय में जून में 607 मरीज भर्ती हुए। इनमें 331 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं 134 मरीज डीओपीआर और आठ मरीज लामा हुए।

▶▶ जो भी रोगी लामा हो रहे हैं, उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वे न जाएं। इसके लिए हमारा स्टाफ भी निगरानी करता है। आगे हम और ज्यादा निगरानी करेंगे जिससे रोगियों को यहीं पर बेहतर इलाज मिल सके।
-डॉ. सीमा श्रीवास्तव, निदेशक, उर्सला

▶▶ हमारे अस्पताल में हड्डी रोग विभाग में अधिकतर रोगी लामा हो रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि रोगी को बेहतर गुणवत्तापूर्ण इलाज मिले और वह अस्पताल छोड़कर न जाए। डीओपीआर में मरीज ठीक होने के बाद घर जाने की इच्छा जताते हैं जिस पर डॉक्टर उनकी रिक्वेस्ट मान लेते हैं।
-डॉ. पीयूष मिश्रा, सीएमएस, कांशीराम अस्पताल

मंडी परिसर में ही निपटाना होगा गीला-सूखा कचरा, नोटिस जारी

बरेली, एजेंसी। शहर की फल एवं सब्जी मंडी में अब कचरा बाहर फेंकने की व्यवस्था समाप्त होगी। नगर निगम ने मंडी से निकलने वाले कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु सख्त रुख अपनाया है। मंडी परिषद को नोटिस जारी कर परिसर में ही गीले और सूखे कचरे का निस्तारण अनिवार्य किया गया है।

नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि फल और सब्जी मंडी से रोज बड़ी मात्रा में जैविक अवशेष उत्पन्न होते हैं। इनके उचित निस्तारण न होने से तीखी दुर्गंध, गंदगी और स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इस स्थिति को रोकने के लिए कचरे का प्रबंधन उसके स्रोत पर ही सुनिश्चित होगा। निगम के नोटिस में सुप्रीम कोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) तथा केंद्र व राज्य सरकार के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन दिशा-निर्देशों का हवाला है। इनके तहत बड़े संस्थानों के लिए कचरे का पृथक्करण और निस्तारण अनिवार्य है।

नगर निगम ने मंडी परिषद को जैविक कचरे से खाद बनाने हेतु परिसर में ही खाद संयंत्र लगाने के निर्देश दिए हैं। इससे कचरे का प्रभावी निस्तारण होगा और तैयार जैविक खाद का व्यावसायिक उपयोग भी संभव होगा। मंडी से निकलने वाले कचरे को अब बाहर नहीं फेंका जा सकेगा। गीले और सूखे कचरे का पृथक्करण और निस्तारण मंडी परिसर के भीतर ही करना होगा। जैविक कचरे से खाद बनाने के लिए खाद संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण नियमों के अनुसार, अधिक कचरा उत्पन्न करने वाले संस्थानों को गीले कचरे का निस्तारण परिसर के भीतर ही करना अनिवार्य है। एनजीटी और शासन के दिशानिर्देशों का मुख्य उद्देश्य कचरे के परिवहन पर निर्भरता घटाना है।

नागर शैली में बनेगा काशी का जगन्नाथ मंदिर, 151 फीट होगी ऊंचाई

वाराणसी , एजेंसी। पुरी के जगन्नाथ धाम की तर्ज पर काशी में जगन्नाथ मंदिर का पुनर्विकास किया जाएगा। मुख्य शिखर की ऊंचाई 151 फीट प्रस्तावित है। इसके तहत करीब एक लाख वर्गफीट क्षेत्र में जगन्नाथ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इसके लिए बुधवार को इंजीनियरों और ग्राफिक्स डिजाइनरों की टीम ने मंदिर पहुंचकर नाप-जोख की। वहीं, राजस्थान से आए शिल्पकारों की टीम ने भी मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। जगन्नाथ मंदिर का स्वरूप इस प्रकार विकसित किया जा रहा है कि मां गंगा में स्नान करने वाले श्रद्धालु नदी तट से ही मंदिर के मुख्य शिखर के दर्शन कर सकेंगे।

परिसर में पारंपरिक ज्ञान और वेदाध्ययन की व्यवस्था भी होगी। दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क महाप्रसाद और भोजन की व्यवस्था रहेगी। साथ ही अत्यंत कम शुल्क पर ठहरने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। निरीक्षण करने वाली टीम में हेड इंजीनियर रजनीकांत उपाध्याय, आर्किटेक्ट अमित कुमार गुप्ता, आर्किटेक्ट जयेश तिवारी, ग्राफिक्स डिजाइनर संजेश मिश्रा, अभिषेक पांडेय और मानसिंह पटेल शामिल रहे। टीम ने निर्माण कार्य की प्रारंभिक रूपरेखा तैयार की। सबसे पहले परिसर में स्थित गरुड़ मंदिर की नाप-जोख की गई।

ट्रस्ट श्री जगन्नाथ जी के सचिव शैलेष त्रिपाठी ने बताया कि मंदिर की मूल संरचना और प्राचीन विग्रहों से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ऐतिहासिक स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए निर्माण कार्य कराया जाएगा। निर्माण कार्य पूरा होने में करीब 41 महीने लगने का अनुमान है। यदि कार्य तय समय पर पूरा हुआ तो दिसंबर 2029 तक मंदिर नए स्वरूप में नजर आएगा।

पहले चरण में निर्माण पर करीब 30 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला की नागर शैली में किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी राजस्थान के शिल्पकार गिरिराज सैनी और उनकी टीम को सौंपी गई है। उनकी टीम में कारीगर विष्णु योगी और अशोक योगी शामिल हैं। धौलपुर (राजस्थान) से लाए गए लाल, गुलाबी और सफेद पत्थरों से मंदिर की नक्काशी और निर्माण कार्य किया जाएगा।

26 जुलाई का सार्वजनिक अवकाश रद्द, आगरा दौरे पर सीएम योगी

53 परियोजनाओं को देंगे हरी झंडी

आगरा, एजेंसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 और 26 जुलाई को आगरा के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह 421.01 करोड़ रुपये की 53 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। दौरे के दूसरे दिन सीएम डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय में कैशलेस योजना का शुभारंभ करेंगे, जबकि प्रशासन और पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 और 26 जुलाई को दो दिवसीय आगरा दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। आगरा में वह 421.01 करोड़ रुपये की 53 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 25 जुलाई को फतेहाबाद रोड स्थित टाटा ग्राउंड में जनसभा होगी, जहां मुख्यमंत्री 37 परियोजनाओं का शिलान्यास और 16 का लोकार्पण करेंगे। 26 जुलाई को डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के खंदारी परिसर में कैशलेस योजना का शुभारंभ करेंगे।

तय कार्यक्रम के अनुसार, शनिवार शाम 4 बजे मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर सीधे टाटा ग्राउंड पहुंचेगा। जनसभा को संबोधित करने से पहले वे यहां सरकारी योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र और नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे जाएंगे। इसके बाद शाम 6 बजे सीएम सर्किट हाउस में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ विकास कार्यों और संगठन को लेकर विशेष बैठक करेंगे।

दौरे के दूसरे दिन, 26 जुलाई को मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में आंबेडकर विश्वविद्यालय के खंदारी परिसर पहुंचेंगे। वे शिवाजी मंडपम सभागार में विवि की बहुप्रतीक्षित कैशलेस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। इसे लेकर विवि प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री के आगमन के कारण शनिवार को सार्वजनिक अवकाश के बावजूद महाविद्यालय के शिक्षकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। अबुल उलाह के उर्स का सार्वजनिक अवकाश था। रविवार को सीएम के दौरे के कारण पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की छुट्टियां भी निरस्त रहेंगी।

राजस्थान में बेची गई थी किशोरी, कपड़े दिलाने के बहाने किया था अगवा

25 हजार की इनामी महिला गिरफ्तार

कानपुर, एजेंसी। कानपुर में नौबस्ता पुलिस ने मानव तस्करी के आरोप में बर्रा के हरदेव नगर निवासी पलक सिंह उर्फ सोनाली अवस्थी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वर्ष 2025 में हंसपुरम की किशोरी को कपड़े दिलाने के बहाने बेहोश कर राजस्थान ले गई, जहां उसे सामूहिक विवाह कराने वाली संस्था की संचालिका को बेच दिया था।

पुलिस ने पलक पर 25 हजार का इनाम घोषित किया था। मामले में पुलिस संस्था की संचालिका और युवती को खरीदने के आरोपी को पहले ही जेल भेज चुकी है। उसे घर से गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा गया। नौबस्ता के हंसपुरम इलाके में रहने वाले मजदूर ने तीन अप्रैल 2025 को थाने में अपनी 16 साल की बेटी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

जयपुर में एक लाख रुपये में बेचा : किशोरी के पिता के अनुसार बेटी घर से कुछ सामान लेने पड़ोस की दुकान गई थी फिर नहीं लौटी। आरोप था कि इलाके का सौरभ मिश्रा 30 मार्च की शाम बेटी को अगवा कर ले गया। पांच अप्रैल को बेटी ने लखनऊ में रहने वाले अपने जीजा को फोन कर बताया कि सौरभ ने उसे अगवाकर राजस्थान के जयपुर के अंखुरिया इलाके में सामाजिक फाउंडेशन चलाने वाली महिला को एक लाख रुपये में बेचा है।

अधेड़ को 2.5 लाख रुपये में बेच दिया था : उस महिला ने शादी के नाम पर नागौर जिले के अधेड़ को 2.5 लाख रुपये में बेच दिया था। किशोरी को बेचे जाने की जानकारी मिलने पर सक्रिय हुई नौबस्ता पुलिस की टीम राजस्थान पहुंची। टीम को किशोरी अंखुरिया के एक घर पर मिली थी। किशोरी की निशानदेही पर पुलिस ने प्रेमनगर पुलिया के पास से उसे खरीदने वाली फाउंडेशन संचालक 52 वर्षीय गायत्री और उसके साथी गागर-बाड़ा निवासी हनुमान को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

कपड़े दिलाने के बहाने साथ ले गई थी : पूछताछ में किशोरी ने बताया कि सौरभ मिश्रा के घर से पलक सिंह उर्फ सोनाली उसे बाजार से कपड़े दिलाने के बहाने साथ ले गई थी। रास्ते में नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया। होश आने पर उसने खुद को राजस्थान में पाया था।

कलुआराम मंडी को लेकर आर-पार की लड़ाई, व्यापारी बोले- कार्रवाई नहीं हुई तो करेंगे भूख हड़ताल

आगरा, एजेंसी। आगरा के बरौली अहीर की नवीन फल एवं सब्जी मंडी में व्यापारी 13 दिनों से धरने पर बैठे हैं और बसई की अवैध मंडियों के साथ कलुआराम मंडी को बंद कराने की मांग कर रहे हैं। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि प्रशासन ने जल्द फैसला नहीं लिया तो वे भूख हड़ताल शुरू करेंगे।

नवीन फल एवं सब्जी मंडी बरौली अहीर में बुधवार को 13वें दिन भी व्यापारियों का धरना जारी रहा। वह बसई में अवैध मंडियों के साथ संचालित कलुआराम मंडी को बंद कराने की मांग पर अड़े हैं। उनका कहना है कि प्रशासन ने जल्द कोई फैसला नहीं लिया तो वह भूख हड़ताल पर बैठेंगे।

मंडी उपाध्यक्ष प्रवेंद्र सिंह ने कहा कि प्रशासन बरौली अहीर मंडी का संचालन शुरू करना चाहता है तो उसे बसई की अवैध मंडियों के साथ कलुआराम मंडी को भी बंद करना ही होगा। उसके लगातार चलने से कोई किसान बरौली अहीर मंडी नहीं आएगा। कलुआराम की मृत्यु के बाद लाइसेंस उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम नहीं आया है। प्रशासन ईमानदारी से सभी तथ्यों को देखकर कलुआराम मंडी को अवैध घोषित कर बंद कराए। ऐसा न करने पर व्यापारी भूख हड़ताल करेंगे।

मुड़िया मेला पर आगरा और मथुरा के बीच चलेंगी तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेन

आगरा, एजेंसी। मुड़िया पूर्णिमा और गोवर्धन परिक्रमा मेले में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने आगरा मंडल से गुजरने वाली ट्रेनों के लिए विशेष व्यवस्था की है। 24 से 31 जुलाई तक आगरा कैंट-मथुरा के बीच तीन जोड़ी मेमू स्पेशल चलाई जाएंगी।

जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि झांसी-आगरा कैंट पैसेंजर का विस्तार डीग तक और नई दिल्ली-आगरा कैंट इंटरसिटी एक्सप्रेस का विस्तार ग्वालियर तक किया गया है। इसके अलावा दक्षिण भारत की चार एक्सप्रेस ट्रेनों को मथुरा और आगरा कैंट पर दो-दो मिनट का अस्थायी ठहराव दिया गया है।

ट्रेन संख्या 11901-11902 झांसी-आगरा कैंट अब 29-30 जुलाई को डीग तक जाएगी। वापसी में 30 व 31 जुलाई को डीग से झांसी चलेगी। ट्रेन 14212-14211 नई दिल्ली-आगरा कैंट इंटरसिटी 24 से 31 जुलाई तक ग्वालियर तक और वापसी में 25 जुलाई से 1 अगस्त तक ग्वालियर से संचालित होगी।

आगरा कैंट से मथुरा के बीच तीन जोड़ी मेमू स्पेशल सुबह 10:35, 11:15 और 11:30 बजे रवाना होकर 12:15, 12:45 और 1:10 बजे मथुरा पहुंचेंगी। वापसी में मथुरा से 12:45, 2:05 और 2:30 बजे चलकर आगरा कैंट 2:40, 4:10 और 4:15 बजे पहुंचेंगी। साथ ही 12652, 12708, 12642 और 12650 एक्सप्रेस को मथुरा और आगरा कैंट पर अस्थायी ठहराव दिया गया है।

कोलकाता इंटरसिटी दो दिन निरस्त अजमेर-सियालदह का बदला रूट : पूर्वी रेलवे के आसनसोल मंडल के मुगमा स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कार्य के चलते सितंबर में आगरा होकर गुजरने वाली चार ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। इसमें आगरा कैंट-कोलकाता इंटरसिटी एक्सप्रेस अप और डाउन में निरस्त रहेंगी, जबकि सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस और अजमेर-सियालदह एक्सप्रेस चार दिनों तक बदले मार्ग से चलेंगी।

आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि ट्रेन संख्या 13167 कोलकाता-आगरा कैंट एक्सप्रेस 24 सितंबर तथा 13168 आगरा कैंट-कोलकाता एक्सप्रेस 26 सितंबर को निरस्त रहेगी। वहीं 12987 सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस 23 से 26 सितंबर तक सीतारामपुर-धनबाद-गया-पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बजाय सीतारामपुर-झाझा-पटना-पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मार्ग से चलेगी। इसी प्रकार 12988 अजमेर-सियालदह एक्सप्रेस भी 23 से 26 सितंबर तक पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन-गया-धनबाद-सीतारामपुर के स्थान पर पटना-झाझा होकर संचालित होगी।

आबूलेन पर घड़ी कारोबारी की दुकान पर पहुंचा युवक, बद्दो के नाम से मांगी एक करोड़ रंगदारी, भीड़ ने धुना

मेरठ, एजेंसी। आबूलेन पर बुधवार को घड़ी कारोबारी नितेश अग्रवाल से एक करोड़ की रंगदारी मांगी गई। एक युवक नशे की हालत में बाइक से घड़ी कारोबारी के पास पहुंचकर उससे कहा कि एक करोड़ की रकम नहीं मिली तो अंजाम सही नहीं होगा। साथ ही रंगदारी मांगने वाले युवक ने पांच लाख के इनामी कुख्यात बदमाश बदन सिंह बद्दो का नाम लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मौके से आरोपी महलवाला किठौर निवासी रोहित त्यागी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

सिविल लाइंस के मोहनपुरी विकासपुरी निवासी नितेश अग्रवाल और नीरज अग्रवाल की आबूलेन पर घड़ी की दुकान है। साथ में फाइनेंस का भी बड़ा काम है। बुधवार दोपहर करीब साढ़े 12 बजे बाइक पर सवार होकर एक युवक नितेश अग्रवाल की दुकान पर पहुंचा। उसने नितेश अग्रवाल से कहा कि एक करोड़ रुपये का इंतजाम कर लो। बदन सिंह बद्दो को यह रकम भेजनी है, समय और दिन बता दिया जाएगा।

कारोबारी ने डायल 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को मौके पर बुला लिया। तब तक आसपास के दुकानदारों ने मिलकर आरोपी युवक को पकड़ लिया। पहले तो उसकी जमकर पिटाई की। उसके बाद सदर बाजार पुलिस के हवाले कर दिया।

पुलिस की जांच में पता चला कि युवक नशे में था। उसे शराब पीने को पैसे चाहिए थे, इसलिए उसने बदन सिंह बद्दो का नाम लेकर रंगदारी मांग ली। पूछताछ में सामने आया कि युवक किठौर के महलवाला का रहने वाला रोहित त्यागी है। रोहित ने पुलिस पूछताछ में बताया कि शराब पीने से के लिए पैसे चाहिए थे। वह खुद मांगता तो कोई पैसे नहीं देता। इसलिए बदन सिंह बद्दो का नाम लेकर रकम मांगी गई थी। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

असम में लगातार हो रही भारी बारिश

सेना ने तेज किया राहत और बचाव अभियान

गुवाहटी, एजेंसी। असम में लगातार हो रही भारी बारिश और नदियों के उफान से उत्पन्न भीषण बाढ़ के बीच भारतीय सेना ने राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। सेना के स्पीयर कोर के अंतर्गत रेड शील्ड डिवीजन के जवान शिवसागर, चराइदेव और जोरहाट जैसे सबसे अधिक प्रभावित जिलों में चौबीसों घंटे राहत कार्यों में जुटे हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, सेना अब तक 700 से अधिक बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा चुकी है, जबकि 150 से अधिक लोगों को चिकित्सा सहायता भी उपलब्ध कराई गई है। परिवारों तक आपातकालीन राशन, स्वच्छ पेयजल और अन्य आवश्यक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। दुर्गम और जलमग्न इलाकों में फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर लगातार हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं।

राहत सामग्री का लगातार वितरण

अधिकारियों ने बताया कि चुनौतीपूर्ण मौसम के बावजूद राहत अभियान जारी हैं, सैनिक जलमग्न गांवों और जलभराव वाले इलाकों में फंसे परिवारों तक पहुंचने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। सेना ने प्रभावित निवासियों को आपातकालीन राशन पैकेट, स्वच्छ पेयजल और अन्य आवश्यक राहत सामग्री भी वितरित की है, जिससे बाढ़ में फंसे लोगों को तत्काल सहायता मिल सके। बचाव प्रयासों को मजबूत करने के लिए सेना के विमानन हेलीकॉप्टर दुर्गम स्थानों में फंसे लोगों की पहचान करने और बाढ़ की स्थिति का आकलन करने के लिए हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। हवाई सर्वेक्षण बचाव दल को बाढ़ के पानी से कटे हुए क्षेत्रों में अभियानों को प्राथमिकता देने में मदद कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय सेना के इंजीनियरों को भी अलग-थलग पड़े गांवों तक संपर्क बहाल करने में सहायता के लिए तैनात किया गया है, ताकि पहुंच मार्गों में सुधार किया जा सके और राहत कार्यों में नागरिक अधिकारियों का सहयोग किया जा सके।

असम में सेना का राहत अभियान तेज

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सेना के स्पीयर कोर के अंतर्गत रेड शील्ड डिवीजन के जवान बाढ़ प्रभावित शिवसागर, चराइदेव और जोरहाट जिलों में चौबीसों घंटे मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान चला रहे हैं, जहां लगातार बारिश और नदियों के उफान से विशाल क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं। सेना ने बताया कि बचाव दल ने बढ़ते बाढ़ के पानी में फंसे 700 से अधिक लोगों को निकाला है, जबकि प्रभावित क्षेत्रों में तैनात फील्ड टीमों के माध्यम से 150 से अधिक निवासियों को चिकित्सा सहायता प्रदान की गई है। जिससे बचाव अभियानों को प्राथमिकता देने में मदद मिल रही है। वहीं, सेना के इंजीनियर अलग-थलग पड़े गांवों तक संपर्क बहाल करने में नागरिक प्रशासन की सहायता कर रहे हैं। राज्य में इस वर्ष की सबसे भीषण बाढ़ से 25 जिले प्रभावित हुए हैं, जहां 72 लाख से अधिक लोग प्रभावित और 31 लोगों की मौत हो चुकी है। सेना ने कहा है कि वह प्रभावित लोगों को समय पर सुरक्षित निकालने और मानवीय सहायता की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नागरिक प्रशासन और अन्य आपदा राहत एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है।

सिक्किम टनल हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 22 हुई, तीन अन्य की तलाश जारी

गंगटोक, एजेंसी। एनएचपीसी तीस्ता स्टेज-6 जलविद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे श्रमिकों की तलाश के लिए राहत एवं बचाव अभियान गुरुवार देर रात तक लगातार जारी रहा। बचाव दलों ने अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच अभियान को जारी रखते हुए शेष लोगों की तलाश के प्रयास तेज कर दिए हैं। रात लगभग 10 बजे पश्चिम बंगाल के आसनसोल से ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) की दूसरी विशेष बचाव टीम घटनास्थल पर पहुंची और तुरंत अभियान में शामिल हो गई। विभिन्न एजेंसियों की टीम समन्वय के साथ मध्यरात्रि तक लगातार राहत एवं बचाव कार्य में जुटी रहीं। ताजा जानकारी के अनुसार, सुरंग से अब तक 22 मृतकों के शव बरामद किए जा चुके हैं। शेष लोगों की तलाश के लिए विशेष बचाव दल लगातार अभियान चला रहे हैं। नामची जिला प्रशासन तथा संबंधित सभी एजेंसियां स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। साथ ही, बचाव कार्य में जुटी टीमों और प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता प्रदान की जा रही है। बता दें कि हादसा सोमवार दोपहर को टनल के अंदरमिथेन गैस रिसाव होने के कारण हुई थी। सोमवार से बचाव और आउद्धार कार्य लगातार चल रही है। एनएनपीसी के आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार टनल के अंदर 25 लोग फंसे हुए थे, गुरुवार सुबह से बांकि के तीन लोगों की तलाशी में टीम जुटी हुई है।

संक्षिप्त समाचार

छात्रों को भड़का कर देश में गृहयुद्ध कराना चाहता है विपक्ष

मुंबई, एजेंसी। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है।

उन्होंने कहा कि संपूर्ण विपक्ष छात्रों और नौजवानों को दिग्भ्रमित करके देश में गृहयुद्ध कराने की साजिश रच रहा है। रोहित सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों और नौजवानों के प्रति संवेदनशील हैं। भारत सरकार के नेतृत्व में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा, 'इनकी सांठ-गांठ विदेशों से है। इनको देश की प्रतिष्ठा, भारतीय संस्कृति और सभ्यता से कोई लेना-देना नहीं है। जिन लोगों ने परिवारवादी राजनीति को अपना आभूषण बनाया है, आज वो भोले-भाले छात्रों को भड़का कर अपनी राजनीतिक रोटी सेंक रहे हैं।' रोहित सिंह ने आगे कहा कि युवा चेतना कश्मीर से कन्याकुमारी तक नौजवानों में जागरूकता अभियान चलाएगी। भारत के छात्रों और नौजवानों का भविष्य प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सुरक्षित है। कांग्रेस और विपक्ष ने हमेशा देश के छात्रों को पीड़ा पहुंचाने का काम किया है।

योगी के नेतृत्व में उप्र ने मारी बाजी; देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स हब

लखनऊ, एजेंसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल करते हुए देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र बनने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाया है। कभी इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के मामले में सीमित पहचान रखने वाला उत्तर प्रदेश आज देश में बनने वाले लगभग 65 प्रतिशत मोबाइल फोन का उत्पादन कर रहा है। यही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट निर्माण में भी प्रदेश की हिस्सेदारी करीब 55 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। इस उपलब्धि ने उत्तर प्रदेश को देश के सबसे बड़े हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित कर दिया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा को केंद्र बनाकर विकसित हुए औद्योगिक इकोसिस्टम ने इस परिवर्तन में सबसे अहम भूमिका निभाई है।

रायपुर में ईडी के खुलासे से करोड़ों के विदेशी ट्रांजेक्शन का खेल, बेरोजगार को बनाया 'डमी डायरेक्टर'

रायपुर, एजेंसी। ईडी की कार्रवाई के बाद रायपुर में करोड़ों रुपये के विदेशी ट्रांजेक्शन का पता चला है। विधानसभा थाना पुलिस ने स्थानीय निवासी संदीप सेठ की शिकायत पर मुंबई के रहने वाले रितेश गुप्ता समेत अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया है। संदीप ने आरोप लगाया है कि उन्हें नौकरी का झांसा देकर एक निजी कंपनी का डायरेक्टर बनाया गया। उनके नाम और कथित फर्जी हस्ताक्षरों का उपयोग कर बैंक खाते संचालित किए गए और उन्हीं खातों के माध्यम से करोड़ों रुपये विदेश भेजे गए। दावा किया कि उन्हें डमी डायरेक्टर की तरह इस्तेमाल किया गया। संदीप ने बताया कि वर्ष 2023 में बेरोजगार होने के दौरान मौसेरे भाई रितेश गुप्ता ने उन्हें ठाणे स्थित कांसलीवाल बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में 50 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन पर डायरेक्टर की नौकरी दिलाई। अधिकांश दस्तावेज उसके घर भेजे जाते थे, जिन पर वह हस्ताक्षर कर वापस भेज देते थे। शिकायत में यह भी कहा गया है कि आरोपित उन्हें मुंबई ले गया, जहां एसबीएम बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक और आरबीएल बैंक में कंपनी के खाते खुलवाए गए। बैंक रिकॉर्ड में उसे अधिकृत लेनदेनकर्ता के रूप में दर्ज किया गया।

अग्निवीरों को तोहफा; छत्तीसगढ़ सरकार इन नौकरियों में देगी 10 फीसदी आरक्षण

रायपुर , एजेंसी। छत्तीसगढ़ सरकार ने अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में दो बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने चार साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को पुलिस, वन और जेल विभाग की सीधी भर्ती में 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया है। सरकार ने किसानों के लिए खाद उपलब्ध कराने को लेकर एक मंत्री-मंडलीय उप समिति गठित करने की भी घोषणा की है।

कैबिनेट ने अग्निवीर सैनिकों को सम्मानजनक रोजगार सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कैबिनेट ने राज्य की तृतीय श्रेणी के पदों (पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी) पर सीधी भर्ती में अग्निवीर सैनिकों के लिए 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान पर मुहर लगाई है।

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ के अग्निवीर सैनिकों के लिए छत्तीसगढ़ की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण नियम-2026 बनाए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इससे सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों में अग्निवीरों को 10 फीसदी कोटा मिलेगा। कैबिनेट ने उक्त निर्णय मुख्यमंत्री की 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के पालन में लिया। इस आरक्षण का लाभ उन अग्निवीर सैनिकों को मिलेगा, जिन्होंने सशस्त्र बलों में चार साल की सेवा पूरी करने के बाद वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ रिटायरमेंट लिया हो। छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसार, इस फैसले से अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सेवाओं में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। इतना ही नहीं अग्निवीर सैनिकों के अनुभव और अनुशासन का लाभ पुलिस, वन एवं जेल प्रशासन को मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में खरीफ और रबी की फसलों के लिए किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने और खाद की आपूर्ति, वितरण और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे पर सुझाव के लिए मंत्री-मंडलीय उप समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस उप समिति में उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग को अध्यक्ष बनाया गया है।

बंधुआ मजदूरी से उत्पाद पर आज आएगी अमेरिकी रिपोर्ट, जद में भारत समेत कितने देश

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका भारत सहित अपने 60 व्यापारिक साझेदार देशों में बंधुआ मजदूरी से तैयार उत्पाद के संबंध में गुरुवार को अंतिम कार्रवाई रिपोर्ट जारी करेगा। अमेरिका ने इन देशों के खिलाफ धारा 301 के तहत जांच की थी। यह कदम सभी देशों पर लगाए गए 10 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ की समय-सीमा समाप्त होने से ठीक पहले उठाया जा रहा है। भारत ने इस जांच का विरोध करते हुए कहा था कि इन मुद्दों पर द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत ही चर्चा की जा सकती है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) जैमीसन ग्रीर ने सीनेट वित्त समिति को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका के शीर्ष 60 व्यापारिक साझेदारों की ओर से अपनी सीमाओं पर बंधुआ मजदूरी से तैयार सामानों के आयात पर रोक न लगाने या उसे प्रभावी ढंग से लागू न कर पाने की जांच की गई थी।

पिछले महीने यूएसटीआर ने देशों के मौजूदा उपायों की कड़ाई के आधार पर 10 फीसदी और 12.5 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया था। ग्रीर ने बताया कि यूएसटीआर को इस पर 1,600 से अधिक आपत्तियां-टिप्पणियां मिली हैं और 107 गवाहों के साथ दूसरे दौर की सुनवाई पूरी की जा चुकी है। भारत ने अमेरिका की इस जांच का विरोध किया है। भारत का कहना है कि इस तरह के मुद्दों पर एकतरफा कार्रवाई करने के बजाय इन्हें भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए। दोनों देशों के बीच इस समझौते पर फिलहाल बातचीत चल रही है। यूएसटीआर ने यह भी बताया कि अमेरिका एक दर्जन से अधिक देशों में अत्यधिक औद्योगिक उत्पादन क्षमता की भी जांच कर रहा है। हालांकि, इस मामले में अभी शुरुआती निष्कर्ष जारी नहीं किए गए हैं। ट्रंप प्रशासन ने यह जांच उस समय शुरू की थी, जब फरवरी 2026 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल लगाए गए पारस्परिक शुल्क को अवैध करार दिया था। इसके बाद प्रशासन ने सभी देशों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया था, जिसकी अवधि शुक्रवार को खत्म हो रही है।

कड़े मुकाबले में एरिजोना में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी चुनाव में भारतवंशी अमीश शाह जीते

फिनिक्स (एरिजोना), एजेंसी। भारतीय मूल के अमीश शाह ने बुधवार को एरिजोना के एक अहम कांग्रेस (संसद) क्षेत्र में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी चुनाव में जीत हासिल की है। यह काफी कड़ा मुकाबला था। शाह की जीत से डेमोक्रेटिक कांग्रेसनल कैंपेन कमेटी (डीसीसीसी) को झटका लगा है, क्योंकि उसने शाह के प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार का समर्थन किया था। यह नतीजा ऐसे समय आया है, जब ज्यादा से ज्यादा मतदाता वाशिंगटन में पार्टी नेताओं की पसंद को खारिज कर रहे हैं।

आपातकालीन चिकित्सक अमीश शाह अब आम चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार जे फीली का सामना करेंगे। फीली नेशनल फुटबॉल लीग (एनएफएल) के पूर्व खिलाड़ी हैं और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइमरी चुनाव में उनका समर्थन किया था। राजनीति में विरोधी बनने से पहले फीली और शाह एक ही टीम न्यूयॉर्क जेट्स का हिस्सा थे। शाह टीम के किनारे तैनात डॉक्टर थे, जबकि फीली टीम के किकर थे। डीसीसीसी ने मार्लीन गैलन-वूड्स का समर्थन किया था। वह पहले रिपब्लिकन पार्टी में थीं और ट्रंप के पहले कार्यकाल की शुरुआत में डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल हो गई थीं।

क्यों अहम माना जा रहा था यह मुकाबला? पहले कांग्रेस क्षेत्र के लिए यह मुकाबला काफी अहम माना जा रहा था। इस क्षेत्र में उत्तर-पूर्वी फीनिक्स, स्कॉट्सडेल, फाउंटेन हिल्स और पैराडाइज वैली जैसे समृद्ध इलाके शामिल हैं। माना जा रहा है कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में किस पार्टी का नियंत्रण रहेगा, इसे तय करने में यह चुनाव भूमिका निभा सकता है। हालांकि, इस क्षेत्र में रिपब्लिकन मतदाता ज्यादा

हैं, लेकिन पिछले एक दशक में यहां के लोगों की राजनीतिक सोच कुछ हद तक बदली है।

यह सीट खाली हुई है क्योंकि रिपब्लिकन सांसद डेविड श्वाइकर्ट ने गवर्नर पद के लिए चुनाव लड़ा था। लेकिन मंगलवार को रिपब्लिकन प्राइमरी में वह एंडी बिग्स से हार गए।

मई में जब डीसीसीसी ने गैलन-वूड्स को समर्थन देने का एलान किया, तो डीसीसीसी की अध्यक्ष और अमेरिकी सांसद सुजान डेलबेनी ने उनके टीवी पत्रकारिता के अनुभव की तारीफ की, लेकिन शाह के बारे में कुछ नहीं कहा।

शाह ने मंगलवार रात समर्थकों से कहा, मैं अपनी पार्टी की पहली पसंद नहीं था। लेकिन मैं पार्टी के स्थापित नेतृत्व के खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार था और यही इस क्षेत्र के मतदाता चाहते हैं।

हालांकि, शाह ने कहा है कि उम्मीदवार बनने के बाद वह डीसीसीसी के साथ काम करेंगे। उन्हें चुनाव जीतने के लिए पार्टी और उसके दानदाताओं के समर्थन की जरूरत होगी, क्योंकि यह मुकाबला मुश्किल माना जा रहा है। इस क्षेत्र में 2024 में ट्रंप को मामूली जीत मिली थी। वहीं, 2020 में पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन ने डेमोक्रेटिक पार्टी से यह क्षेत्र जीता था, जबकि श्वाइकर्ट दोबारा सांसद चुने गए थे। डीसीसीसी के गैलन-वूड्स को समर्थन देने के फैसले से स्थानीय डेमोक्रेट्स हैरान थे। इसकी वजह यह थी कि गैलन-वूड्स और शाह की राजनीतिक सोच में ज्यादा अंतर नहीं था। दोनों ही बीच की राजनीतिक सोच रखने वाले उम्मीदवार हैं। यह चुनाव डेमोक्रेटिक पार्टी में बढ़ते प्रगतिशील और मध्यमार्गी नेताओं के बीच विवाद का हिस्सा भी नहीं था। यह मुकाबला कुछ हद तक 2024 के चुनाव जैसा था। उस समय शाह ने कई उम्मीदवारों के बीच हुए प्राइमरी मुकाबले में मामूली अंतर से जीत हासिल की थी। उस चुनाव में गैलन-वूड्स भी शामिल थीं। हालांकि, आम चुनाव में शाह हार गए थे।

ट्रांसजेंडर सैनिकों के इलाज व टेस्टोस्टेरोन नीति में क्या फर्क, जज ने ट्रंप प्रशासन पर उठाए सवाल

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की नई टेस्टोस्टेरोन जांच और उपचार पहल पर एक संघीय जज ने सवाल उठाए हैं। जज ने पूछा कि सैनिकों में कम टेस्टोस्टेरोन के उपचार और ट्रांसजेंडर सैनिकों को दिए जाने वाले हार्मोन उपचार में आखिर अंतर क्या है। यह सवाल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस नीति पर चल रहे मुकदमे के दौरान उठा, जिसमें ट्रांसजेंडर सैनिकों पर रोक लगाई गई है। वाशिंगटन की अमेरिकी जिला जज एना रेयेस ने कहा कि ट्रंप की नीति में लिखा है कि सशस्त्र बलों को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के ऊंचे मानकों का पालन करना चाहिए। इसके लिए नियमित इलाज या विशेष व्यवस्था पर निर्भर नहीं होना चाहिए। जज ने मुकदमे से जुड़े दोनों पक्षों को निर्देश दिया कि वे बताएं कि ट्रांसजेंडर पुरुषों और अन्य सैनिकों को टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देने में चिकित्सकीय और व्यावहारिक स्तर पर क्या समानताएं और क्या अंतर हैं। उन्होंने रक्षा मंत्रालय से यह भी जानकारी मांगी कि नई टेस्टोस्टेरोन नीति और ट्रांसजेंडर सैनिकों पर रोक के बीच अलग-अलग व्यवहार का आधार क्या है। रक्षा मंत्री की नई पहल क्या है यह आदेश उस घोषणा के एक सप्ताह बाद आया है, जिसमें रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने सैनिकों में टेस्टोस्टेरोन की कमी की जांच के लिए नया कार्यक्रम शुरू करने की बात कही थी। उन्होंने बताया था कि 30 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सैनिकों की हर साल होने वाली अनिवार्य स्वास्थ्य जांच के दौरान यह जांच भी की जाएगी। 30 वर्ष से कम उम्र के सैनिक अपनी इच्छा से यह जांच करा सकेंगे। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में हेगसेथ ने कहा था कि टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेना पूरी तरह स्वैच्छिक होगा। ट्रंप प्रशासन के दूसरे अधिकारी भी पुरुषों के लिए टेस्टोस्टेरोन उपचार को आसान बनाने की वकालत कर रहे हैं। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि इस विषय पर वैज्ञानिक तथ्यों के साथ कुछ ऐसे दावे भी किए जा रहे हैं, जिनके पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं। पुरुषों में उम्र बढ़ने के साथ टेस्टोस्टेरोन का स्तर स्वाभाविक रूप से कम होता है।

अमेरिका के मैडिसन में पुलिस पर फायरिंग

गिरफ्तारी के दौरान अधिकारी पर किया हमला, जवाबी कार्रवाई में आरोपी ढेर

मैडिसन, एजेंसी। मैडिसन के एक पुलिस अधिकारी ने एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी। क्योंकि पीड़ित ने अपनी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए पुलिस को चाकू से घायल कर दिया था। यह जानकारी शहर के पुलिस प्रमुख ने दी। घटना के तुरंत बाद गोलीबारी का मोबाइल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में तीन गोलियों की आवाज सुनी जा सकती है। मैडिसन पुलिस प्रमुख जॉन पैटरसन ने एक संवाददाता सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया कि प्रसारित हो रहा फुटेज घटना का सिर्फ एक पहलू है। पैटरसन ने कहा 'मैं इस दुखद घड़ी में उनके परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। पैटरसन ने बताया कि मृतक की उम्र 30 वर्ष के आसपास थी, लेकिन पुलिस ने उसका नाम जारी नहीं किया। यह गोलीबारी राज्य की राजधानी से दो मील से भी कम दूरी पर स्थित एक लोकप्रिय इलाके की सड़क पर हुई, जहां रेस्तरां, बार, दुकानें और आवासीय मकानों की भरमार है। घटना के फुटेज में चौराहे पर कई कारें रुकी हुई दिखाई दे रही हैं और

लोग घटनाक्रम को अपनी आंखों से देख रहे हैं। 2015 में, उसी सड़क पर एक श्वेत पुलिस अधिकारी ने टोनी रॉबिन्सन, जो मिश्रित नस्ल के थे उसको गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। जिला अटॉर्नी ने उस घटना में पुलिस के खिलाफ कोई आरोप दायर नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अधिकारी की कार्रवाई को उचित ठहराया था। बुधवार को गोली चलाने वाले अधिकारी और गोली लगने से मारे गए व्यक्ति की नस्ल के बारे में पुलिस ने कोई जानकारी जारी नहीं की। लेकिन मैडिसन में अश्वेत समुदाय के समर्थकों ने कहा कि मरने वाला व्यक्ति अश्वेत था। मैडिसन स्थित अश्वेत समुदाय के हिमायती समूह अर्बन ट्रायज की प्रमुख ब्रांडी ग्रेसन ने कहा 'मैडिसन की एक सड़क पर एक और अश्वेत व्यक्ति की मौत हो गई। हमारे समुदाय ने उसका नाम जानने से पहले ही उसे मरते हुए देखा। यह राज्य हिंसा की क्रूरता है।' पैटर्सन ने बताया कि पुलिस को पड़ोस में खड़ी गाड़ियों में घुसने की कोशिश करने की सूचना मिली थी। पैटर्सन ने बताया कि संदिग्ध पुलिस अधिकारियों के सड़क पर संपर्क करने से पहले पास के पिछे से होते हुए बाइक पर भाग निकला। पैटर्सन ने बताया कि संदिग्ध या तो अपनी बाइक से गिर गया या अधिकारियों ने उसे बाइक से नीचे उतारा और हाथापाई के दौरान उसने चाकू निकालकर एक अधिकारी को घायल कर दिया।

संपादकीय

टकराव से नहीं चलेगा लोकतंत्र...

यह एक आदर्श स्थिति है कि देश की संसद में विधायी कामकाज सामान्य तरीके से पूरा हो। इसे सुनिश्चित करने की जितनी जिम्मेदारी विपक्षी दलों की है, उससे ज्यादा बड़ा दायित्व खुद सरकार का है कि वह विवादित मुद्दों पर संवाद के जरिए आमराय बनाकर सदन का काम सुचारु रूप से पूरा होने की स्थितियां निर्मित करे।

इसमें वैसे मुद्दे भी शामिल हैं, जो देश में किन्हीं वजहों से अचानक खड़े हो जाते हैं और जनता की ओर से उन पर सरकार से जवाब की उम्मीद या मांग की जाती है। विपक्षी दलों का कर्तव्य है कि वे जनता की नुमाइंदगी करते हुए उनकी आवाज, उनके मुद्दों को संसद में उठाएं और सरकार से जवाब मांगें। मगर इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि सरकार को इस तरह की स्थितियों में सकारात्मक माहौल बनाने के लिए अपनी ओर से पहल करना कोई गैर-महत्त्व की बात लगती है। इसका असर संसद की कार्यवाही पर भी पड़ता है। सवाल है कि देश की संसद अगर जनता के मुद्दों पर विचार और बहस के जरिए किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए नहीं, तो आखिर किसलिए है!

गौरतलब है कि मंगलवार को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही इसलिए स्थगित कर दी गई कि विपक्षी दल सरकार से इस पर जवाब चाहते थे कि एक दिन पहले दिल्ली में संसद मार्च के आह्वान के तहत जुटे युवाओं पर जिस तरह की पुलिस कार्रवाई देखी गई, उसकी जिम्मेदारी तय हो। मगर इसके बजाय दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हुए हंगामे की वजह से कार्यवाही स्थगित कर दी गई। स्वाभाविक ही विपक्षी दलों को यह आरोप लगाने का मौका मिला

कि हम पुलिस के अत्याचार, प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर लाठी चलाने और उनके घायल होने के मुद्दे पर सदन में चर्चा कराने तथा गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने चर्चा का अवसर नहीं दिया, हमारा मुंह बंद करा दिया।

एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष की ओर से अगर ऐसे सवाल उठाए जाते हैं, तो सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। विडंबना यह है कि न तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे आंदोलनकारियों से संवाद स्थापित करके कोई हल निकालने की कोशिश की गई और न ही संसद में इस मसले पर बहस के लिए सकारात्मक माहौल निर्मित किया जा रहा है।

सवाल है कि अगर सरकार को बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकालना प्राथमिक और जरूरी नहीं लग रहा है, तो उसकी नजर में इसका क्या समाधान है। विपक्षी दल भी आम नागरिकों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर वे एक ज्वलंत मुद्दे पर बहस चाहते हैं और सरकार से जवाब मांग रहे हैं, तो इसे संवाद के रास्ते ही एक निष्कर्ष तक पहुंचाया जा सकता है।

इसके बाद संसद में बाकी विधायी कामकाज भी सहजता के साथ निपटाए जा सकते हैं। मगर पिछले कुछ समय से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ज्यादातर मुद्दों पर मतभिन्नता सीधे टकराव का रूप लेने लगी है और सबसे आसान उपाय सदन को स्थगित करना मान लिया जाता है।

क्या यह समस्याओं का हल तलाशने और जनभावनाओं को तुष्ट करने का कोई आदर्श उपाय हो सकता है? दोनों सदनों की कार्यवाही पर हर रोज करोड़ों रुपये का खर्च आता है। संसद की उपयोगिता का आधार लोकतांत्रिक संवाद ही है। अगर संवाद की जगह सिकुड़ेगी, तो लोकतंत्र कमजोर होगा और यह ध्यान रखने की जरूरत है कि देश की वास्तविक शक्ति लोकतंत्र में ही निहित है।

विदेशों में भारतीयों की सुरक्षा पर फिर उठे सवाल

भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग बेहतर रोजगार के लिए विदेश जाते हैं और वहां से विदेशी मुद्रा यहां भेजते हैं। इससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार को भी मजबूती मिलती है। मगर सवाल है कि विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? यूक्रेन के तट से रवाना हो रहे गिनी-बिसाऊ के ध्वज वाले एक वाणिज्यिक जहाज पर हाल ही में हुए हमले में चार भारतीय नागरिकों की मौत की घटना से यह सवाल एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है। इससे पहले होर्मुज जलमार्ग में तेल के एक जहाज पर हुए हमले में भारतीय नागरिक की मौत हो गई थी। हालांकि, विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन की घटना पर नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास के प्रभारी अधिकारी को तलब कर अपना विरोध दर्ज कराया है, लेकिन क्या इससे यह सुनिश्चित हो पाएगा कि भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं होगी। जाहिर है, भारत को ऐसे मामलों में कड़ा रुख अपनाना चाहिए और पीड़ित परिवारों को भी हरसंभव सहायता मुहैया कराने को प्राथमिकता दी जानी

चाहिए। गौरतलब है कि बीती 19 जुलाई की शाम को एमवी गोल्डन लियो नामक वाणिज्यिक जहाज पर यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से रवाना होते समय हमला हुआ था। उस वक्त जहाज पर चालक दल के सत्रह सदस्य सवार थे, जिनमें चार भारतीयों समेत दस लोगों की मौत हो गई, जबकि एक भारतीय नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गया। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय का दावा है कि यह हमला रूसी सेना की ओर से किया गया। रूस-यूक्रेन युद्ध में भारतीय नाविकों की मौत का यह पहला मामला है।

मगर सवाल है कि युद्ध के नियमों के विपरीत किसी असैन्य जहाज को निशाना क्यों बनाया गया? जबकि उस पर झंडा भी किसी तीसरे देश का लगा हुआ था। दूसरा, भारत सरकार को इस बात पर भी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि अपने देश के नागरिकों को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में युद्ध के प्रभाव वाले क्षेत्रों से कैसे दूर रखा जाए। साथ ही इस तरह के हमलों में पीड़ित परिवारों की मदद और मृतकों के शव शीघ्र स्वदेश लाने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया जाना चाहिए।

आज का कार्टून

सीजेपी के संसद मार्च से सुलगते सवाल और राजनीतिक निहितार्थ

यदि संसद मार्च के घटनाक्रमों पर संतुलित नजर डालें तो यही प्रतीत होता है कि जब बड़ी संख्या में सीजेपी (सीजेपी) समर्थक 'संसद चलो' मार्च के लिए जंतर-मंतर से संसद की ओर बढ़े, तो भले ही उनकी मुख्य मांगें शिक्षा सुधार, परीक्षा-पत्र लीक और जवाबदेही था, लेकिन इरादे तोड़फोड़ वाले और खतरनाक थे, अन्यथा पुलिस को बल प्रयोग नहीं करना पड़ता। चूंकि संसद के मानसून सत्र के दौरान माननीयों की सुरक्षा के दृष्टिगत दिल्ली पुलिस ने व्यापक बैरिकेडिंग की थी, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को रोका, हिरासत में लिया तथा कुछ स्थानों पर आंदोलनकारियों द्वारा उपद्रव करने के बाद आंसू गैस और बल प्रयोग की घटनाएं सामने आईं। इससे अफरातफरी मच गई। देखा जाए तो इस आंदोलन की प्रमुख मांगों में नीट पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं पर कार्रवाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार की जवाबदेही, कुछ नेताओं द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग, आंदोलन से जुड़े लोगों के साथ संवाद आदि हैं, लेकिन जो उत्पात दिखाई-सुनाई दिया, वह विपक्षी संस्कार नहीं तो क्या है? फिर भी, केंद्र सरकार ने आंदोलन के प्रतिनिधियों से बातचीत की पहल भी की, जो टकराव के बीच संवाद की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा सकता है।

कमलेश पांडे

कॉकरोच जनता पार्टी का 'संसद चलो' आह्वान केवल एक विरोध मार्च नहीं, बल्कि केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की एक राजनीतिक रणनीति है। खासकर जिस तरह से इस आंदोलन को छात्र आंदोलन का स्वरूप दिलवाया जा चुका है, वह डीप स्टेट के इशारे पर बनी विपक्ष की शातिर सरकार घेरो रणनीति का कमाल भी करार दिया जा रहा है। देखा जाए तो संसद के मानसून सत्र के दौरान गत 20 जुलाई को जंतर-मंतर से संसद की ओर मार्च करने के दौरान बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे और कूच किया, वह बिल्कुल संगठित राजनीतिक आंदोलन के तर्ज पर हुआ। वायुमण्डलविज्ञान

मजे की बात तो यह कि संसद के निकट पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जो पूर्व प्रायोजित झड़प हुई और उसके बाद हालात नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, इससे यह संसद मार्च राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बन गया। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स और अखबारों के दफ्तरों में इससे जुड़े कई नीतिगत सवालों पर भी बहस होने लगी। सोशल मीडिया पर जहां सरकार विरोधी भड़काऊ वीडियो वायरल होने लगे, वहीं सत्ताधारी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी आंदोलनकारियों की कारगुजारियों के वीडियो साझा कर दिए, जिससे लोगों की सहानुभूति पुलिस और सरकार के साथ बनी रही।

यदि संसद मार्च के घटनाक्रमों पर संतुलित नजर डालें तो यही प्रतीत होता है कि जब बड़ी संख्या में सीजेपी (सीजेपी) समर्थक 'संसद चलो' मार्च के लिए जंतर-मंतर से संसद की ओर बढ़े, तो भले ही उनकी मुख्य मांगें शिक्षा सुधार, परीक्षा-पत्र लीक और जवाबदेही था, लेकिन इरादे तोड़फोड़ वाले और खतरनाक थे, अन्यथा पुलिस को बल प्रयोग नहीं करना पड़ता। चूंकि संसद के मानसून सत्र के दौरान माननीयों की सुरक्षा के दृष्टिगत दिल्ली पुलिस ने व्यापक बैरिकेडिंग की थी, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को रोका, हिरासत में लिया तथा कुछ स्थानों पर आंदोलनकारियों द्वारा उपद्रव करने के बाद आंसू गैस और बल प्रयोग की घटनाएं सामने आईं। इससे अफरातफरी मच गई।

देखा जाए तो इस आंदोलन की प्रमुख मांगों में नीट पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं पर कार्रवाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार की जवाबदेही, कुछ नेताओं द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग, आंदोलन से जुड़े लोगों के साथ संवाद आदि हैं, लेकिन जो उत्पात दिखाई-सुनाई दिया, वह विपक्षी संस्कार नहीं तो क्या है? फिर भी, केंद्र सरकार ने आंदोलन के प्रतिनिधियों से बातचीत की पहल भी की, जो टकराव के बीच संवाद की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा सकता है। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा ने सरकारी प्रतिनिधि के तौर पर सीजेपी प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की और मांगपत्र ग्रहण किया। बावजूद इसके आंदोलनकारी अपनी मांगों पर कायम हैं।

सवाल है कि संसद मार्च के क्रम में जो कुछ गड़बड़ हुआ, क्या वह लोकतांत्रिक है, सही था या गलत? तो जवाब होगा कि युवाओं का शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा की निष्पक्षता जैसे मुद्दों पर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ उठाना लोकतंत्र का वैध हिस्सा है। वहीं, सरकार द्वारा आंदोलनकारियों से बातचीत शुरू करना भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुरूप कदम है। फिर भी संसद मार्च के दौरान आंदोलनकारियों की ओर से कुछ कुछ गलत हुआ जो अनुचित लगा। यदि प्रदर्शनकारियों ने निषिद्ध क्षेत्र में जबरन प्रवेश करने या बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, तो वह कानून-व्यवस्था की दृष्टि से उचित नहीं माना जाएगा। वहीं, यदि पुलिस ने आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया या शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर अनावश्यक कार्रवाई हुई, तो उसकी भी निष्पक्ष जांच और जवाबदेही तय होनी चाहिए। हालांकि, इस पर अलग-अलग पक्षों के अपने अपने दावे हैं और सभी तथ्यों के गोलमोल जवाब ही मिले हैं, जिनपर एतबार करना

मुश्किल है क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, जिसका अंतिम सत्यापन अभी होना बाकी है, कई अनकही कहानियां गढ़ रहे हैं। इससे सरकार सांसत में है और विपक्ष तरह-तरह के आरोप लगाकर सिस्टम की मुश्किलें बढ़ा रहा है। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं कि लोकतांत्रिक समाधान का सर्वोत्तम रास्ता संवाद और कानून के दायरे में रहकर समस्या का समाधान है।

भले ही किसी भी लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन और अपनी मांगें रखना नागरिकों का अधिकार है, लेकिन इस संसद मार्च के क्रम में देश की राजधानी नई दिल्ली के हृदय स्थल पर, जिस प्रकार की हिंसा, तोड़फोड़, सार्वजनिक व निजी संपत्ति को नुकसान पहुँचाना या सुरक्षा बलों से टकराव की जो प्रवृति दिखाई दी, वह विपक्षी दलों का परोक्ष कुचक्र नहीं तो क्या है? आखिर इस देशद्रोही प्रवृति को कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इसी प्रकार, यदि पुलिस बल का प्रयोग आवश्यकता से अधिक हुआ हो, तो उसकी भी निष्पक्ष समीक्षा होनी चाहिए। सवाल है कि क्या स्थानीय जिलाधिकारी और डीसीपी के पास छात्र समूह को काबू में रखने की कोई स्पष्ट रणनीति नहीं थी? और यदि थी तो फिर इतना सबकुछ कैसे हुआ? वहीं कोई पुलिस कर्मी कैसे पिट गया और घायल हुआ? आखिर किसी दुकानदार को तोड़-फोड़ का सामना क्यों और कैसे करना पड़ा? जनपथ बाजार की सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त क्यों नहीं किए गए थे। वहीं, अनियंत्रित युवा भीड़ क्यों जुटने दी गई और उनको काबू में रखने के लिए व्यापक बंदोबस्त क्यों नहीं किये गए थे?कॉकरोच जनता पार्टी के 'संसद चलो' आह्वान के राजनीतिक मायने केवल एक विरोध मार्च तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह भारतीय राजनीति में युवाओं के असंतोष, डिजिटल आंदोलन और पारंपरिक दलों के प्रति अविश्वास का प्रतीक बनकर उभरा है। हालांकि सीजेपी स्वयं को व्यंग्यात्मकआंदोलन बताता है, लेकिन इसके मुद्दे गंभीर राजनीतिक प्रश्न उठाते हैं। दक्षिण-एशियाईऔर प्रवासी यही वजह है कि राजनीतिक दृष्टि से इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं:- पहला, संसद के मानसून सत्र के पहले दिन दबाव की राजनीति। दूसरा, युवाओं और प्रतियोगी परीक्षा अभ्यर्थियों के असंतोष को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का प्रयास। तीसरा, विपक्ष के लिए सरकार को घेरने का अवसर और चौथा, सरकार के लिए कानून-व्यवस्था बनाए रखते हुए आंदोलनकारियों से संवाद की चुनौती आदि। एक, युवा असंतोष का राजनीतिक रूपांतरणः बेरोज़गारी, परीक्षा-पत्र लीक, शिक्षा व्यवस्था और राजनीतिक जवाबदेही जैसे मुद्दों को लेकर नाराज़गी को संगठित करने का प्रयास दिखाई देता है। दो, डिजिटल से सड़क तकः सोशल मीडिया पर शुरू हुआ अभियान अब वास्तविक जन-प्रदर्शन में बदलता दिख रहा है, जो यह संकेत देता है कि ऑनलाइन असंतोष भी राजनीतिक दबाव का माध्यम बन सकता है।

तीन, सरकार पर दबावः संसद के मानसून सत्र के पहले दिन मार्च का समय चुनना सरकार और संसद का ध्यान आकर्षित करने की रणनीति माना जा सकता है। सरकार और सीजेपी प्रतिनिधियों के बीच बातचीत शुरू होने की खबर भी इसी दबाव का संकेत है। चार, विपक्ष के लिए अवसरः यदि विपक्ष इस असंतोष को राजनीतिक समर्थन देता है, तो यह सरकार को घेरने का एक नया मुद्दा बन सकता है। वहीं यदि आंदोलन स्वतंत्र बना रहता है, तो यह पारंपरिक दलों से अलग एक नई राजनीतिक शैली का संकेत होगा।

पांच, प्रतीकों की राजनीतिः 'कॉकरोच' जैसे अपमानजनक शब्द को पहचान और प्रतिरोध के प्रतीक में बदलना राजनीतिक संचार की एक प्रभावी रणनीति है, जो विशेषकर युवाओं के बीच ध्यान आकर्षित करती है। छठा, सीजेपी की कई मांगें और उसकी प्रस्तुति व्यंग्य एवं प्रतीकात्मक राजनीति का हिस्सा हैं। इसलिए यह कहना अभी जल्दबाज़ी होगी कि यह एक स्थायी राष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति बन जाएगी। दरअसल उसकी वास्तविक राजनीतिक क्षमता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या वह सोशल मीडिया की लोकप्रियता को लंबे समय तक संगठित जनसमर्थन और ठोस राजनीतिक संगठन में बदल पाती है।

निष्कर्षतः यही कहना उपयुक्त होगा कि लोकतंत्र में न तो हिंसक टकराव समाधान है और न ही वैध असंतोष को केवल बल पूर्वक दबाना। लिहाजा सबसे उचित रास्ता यही है कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहे, कानून का सम्मान हो, और सरकार ठोस संवाद के माध्यम से शिक्षा सुधार तथा परीक्षा प्रणाली से जुड़े मुद्दों का विश्वसनीय समाधान प्रस्तुत करे। अन्यथा छात्र आंदोलन यदि राष्ट्रीय स्वरूप अख्तियार कर लेगा तो सनातनी सत्ता को लेने के देने पड़ जाएंगे।

अतीत के पछतावे में वर्तमान का सबसे अनमोल समय न खो दें

कभी-कभी जीवन में सबसे बड़ी कमी समय की नहीं, बल्कि ध्यान की होती है। हमारे पास वही चौबीस घंटे होते हैं, जो संसार के हर व्यक्ति के पास हैं। अंतर केवल इतना होता है कि हम उन्हें किस प्रकार जीते हैं। जो व्यक्ति वर्तमान के प्रति सजग होता है, वह सीमित परिस्थितियों में भी संतोष और अर्थ खोज लेता है। आखिर जीवन कोई ऐसी मंजिल नहीं है, जहां पहुंचने के बाद हम जीना शुरू करेंगे। जीवन तो हर दिन, हर क्षण हमारे सामने खुलता रहता है। आवश्यकता केवल इतनी है कि हम उसे देखने, समझने और महसूस करने के लिए स्वयं को तैयार करें। जरूरी है कि हम वर्तमान को केवल गुजारें नहीं, बल्कि उसे पूरी सजगता, संवेदना और कृतज्ञता के साथ जिएं। शायद यही जीवन को समझने की सबसे बड़ी कला है।

संध्या अग्रवाल

मनुष्य के जीवन की एक अजीब विडंबना है कि वह जिस समय को सबसे अधिक मूल्यवान मानता है, उसी समय को सबसे अधिक खो देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन तब बेहतर होगा, जब कोई विशेष परिस्थिति आएगी, कोई लक्ष्य पूरा होगा या कोई बड़ी उपलब्धि हमारे हिस्से में आएगी। इसी प्रतीक्षा में वह समय निकल जाता है, जो वास्तव में हमारे पास था।

जीवन हमेशा वर्तमान में घटता है, लेकिन हमारा मन अक्सर या तो बीते हुए कल में उलझा रहता है या आने वाले कल की चिंता में भटकता रहता है। अतीत का अपना महत्त्व है। वह हमें अनुभव देता है, हमारी गलतियों से परिचित कराता है और आगे बढ़ने की समझ विकसित करता है। इसी तरह भविष्य के लिए योजना बनाना भी आवश्यक है, क्योंकि वही हमें दिशा देता है। समस्या तब पैदा होती है, जब अतीत का बोझ और भविष्य की चिंता वर्तमान की सुंदरता को ढकने लगती है। तब हमारे पास जीवन तो होता है, लेकिन उसे महसूस करने का समय नहीं होता। बचपन में मनुष्य वर्तमान को स्वाभाविक रूप से जीता है। छोटी-सी खुशी भी उस समय जीवन का बड़ा उत्सव लगती है। बारिश की बूंदें, दोस्तों के साथ खेलना, परिवार के साथ बिताया गया समय या किसी छोटी उपलब्धि पर मिली प्रशंसा मन को प्रसन्न कर देती थी, लेकिन जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, जिम्मेदारियां बढ़ने लगती हैं और मनुष्य भविष्य की योजनाओं तथा चिंताओं में अधिक उलझने लगता है। धीरे-धीरे वह उस सहजता को खो देता है, जिसमें जीवन का वास्तविक आनंद छिपा होता है।

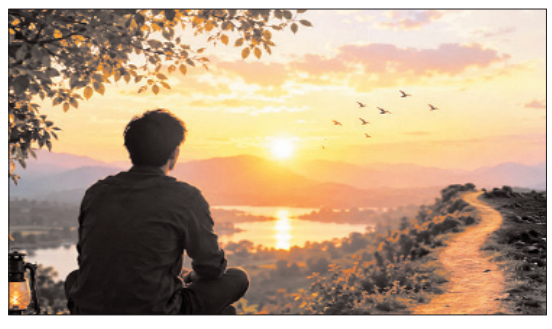

आज तेज गति का दौर है। हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। बेहतर करियर, अधिक सुविधाएं, सामाजिक पहचान और आर्थिक सुरक्षा की इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन परेशानी तब शुरू होती है, जब भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश में वर्तमान ही उपेक्षित हो जाता है। हम उस कल के लिए आज को टालते रहते हैं, जो आने के बाद फिर एक नया कल बन जाएगा।

आधुनिक जीवन ने इस स्थिति को और जटिल बना दिया है। तकनीक ने हमारी दुनिया को सुविधाजनक बनाया है, लेकिन साथ ही हमारा ध्यान भी कई दिशाओं में बांट दिया है। हम हर समय किसी न किसी सूचना, संदेश या गतिविधि से जुड़े रहते हैं। ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन भीतर से कई बार यह अनुभव होता है कि हम अपने ही जीवन से जुड़ नहीं पा रहे हैं।

कई बार परिवार के लोग एक ही स्थान पर बैठे होते हैं, लेकिन सब अपने-अपने डिजिटल संसार में व्यस्त होते हैं। हम किसी सुंदर क्षण को कैमरे में कैद करने की चिंता तो करते हैं, लेकिन उस क्षण को मन में उतारना भूल जाते हैं। जीवन की वास्तविक अनुभूति तस्वीरों में नहीं, बल्कि उस पल को पूरी संवेदना के साथ जीने में होती है। वर्तमान में उपस्थित रहना किसी विशेष परिस्थिति या सुविधा का नाम नहीं है। इसके लिए किसी उपलब्धि की आवश्यकता नहीं होती। यह जीवन के साधारण क्षणों को महत्त्व देने की समझ है। सुबह की शांति, किसी अपने का स्नेह, अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना, किसी जरूरतमंद की सहायता करना या अपनी छोटी-सी सफलता पर संतोष महसूस करना-यही वे पल हैं, जो जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। अक्सर मनुष्य यह मान लेता है कि खुशी किसी भविष्य की मंजिल पर उसका इंतजार कर रही है। वह सोचता है कि जब सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, तब वह चैन से जी पाएगा। जीवन का अनुभव बताता है कि समस्याएं कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होतीं। वर्तमान को जीने का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति भविष्य की चिंता छोड़ दे या अपने दायित्वों से मुक्त हो जाए। बस जो समय हमारे सामने है, उसे पूरी सजगता के साथ जिया जाए। जो व्यक्ति आज को बेहतर बनाता है, वही अपने आने वाले समय की नींव मजबूत करता है।

कई बार हम अपने प्रिय लोगों के साथ होते हुए भी पुराने दुखों या आने वाली चिंताओं में उलझे रहते हैं। परिणाम यह होता है कि सामने मौजूद प्रेम और अपनापन हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। रिश्ते केवल साथ रहने से मजबूत नहीं होते, बल्कि एक-दूसरे को समय देने और समझने से मजबूत होते हैं। समय की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह लौटकर नहीं आता। जो क्षण आज हमारे पास हैं, वे कल केवल स्मृतियां बन जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम अपने जीवन में उपस्थित लोगों और परिस्थितियों का मूल्य समय रहते समझें। कई बार हमें किसी चीज की वास्तविक कीमत उसके दूर चले जाने के बाद समझ आती है, लेकिन तब केवल पछतावा शेष रह जाता है।

अब यह विचार भी आवश्यक है कि विकास केवल अधिक सुविधाएं जुटाने का नाम नहीं है। जीवन की गुणवत्ता इस बात से भी तय होती है कि हम अपने अनुभवों को कितनी गहराई से महसूस करते हैं। साधनों की वृद्धि के साथ अगर मनुष्य भीतर से असंतुष्ट और अनुपस्थित होता जा रहा है, तो उसे अपने जीवन जीने के तरीके पर विचार करना होगा।

कभी-कभी जीवन में सबसे बड़ी कमी समय की नहीं, बल्कि ध्यान की होती है। हमारे पास वही चौबीस घंटे होते हैं, जो संसार के हर व्यक्ति के पास हैं। अंतर केवल इतना होता है कि हम उन्हें किस प्रकार जीते हैं। जो व्यक्ति वर्तमान के प्रति सजग होता है, वह सीमित परिस्थितियों में भी संतोष और अर्थ खोज लेता है। आखिर जीवन कोई ऐसी मंजिल नहीं है, जहां पहुंचने के बाद हम जीना शुरू करेंगे। जीवन तो हर दिन, हर क्षण हमारे सामने खुलता रहता है। आवश्यकता केवल इतनी है कि हम उसे देखने, समझने और महसूस करने के लिए स्वयं को तैयार करें। जरूरी है कि हम वर्तमान को केवल गुजारें नहीं, बल्कि उसे पूरी सजगता, संवेदना और कृतज्ञता के साथ जिएं। शायद यही जीवन को समझने की सबसे बड़ी कला है।

भारत का पहला पदक पक्का

लवलीना सेमीफाइनल में पहुंचीं

ग्लासगो (एजेंसी)। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की ओपनिंग सेरेमनी से पहले ही भारत ने अपना पहला पदक सुनिश्चित कर लिया है। ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को 'बाय' मिला है। इसके माध्यम से सीधे सेमीफाइनल में पहुंचते हुए उन्होंने अपना पदक सुनिश्चित कर लिया। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन 'बाय' मिलने के बाद महिलाओं के 75 किग्रा कैटेगरी के सेमीफाइनल में सीधे पहुंची। ड्रॉ में सिर्फ पांच एथलीट थे, इसलिए लवलीना समेत तीन खिलाड़ी सीधे 'अंतिम-4' (सेमीफाइनल) में पहुंच गए, जबकि बाकी दो खिलाड़ियों को एकमात्र क्वार्टरफाइनल मैच खेलना था। कॉमनवेल्थ गेम्स के बॉक्सिंग नियमों के तहत, सेमीफाइनल में हारने वाले सभी खिलाड़ियों को कांस्य पदक दिया जाता है। इसका मतलब है कि ग्लासगो में अपना पहला मुकाबला खेलने से पहले ही लवलीना का कांस्य पदक पक्का हो गया है।

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026

लवलीना 31 जुलाई को सेमीफाइनल में ताफाकी के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी, जहां स्वर्ण पदक मैच में जगह बनाने का मौका होगा। जीत उन्हें फाइनल में पहुंचाएगी और कम से कम रजत पदक पक्का करेगी, जबकि हारने पर भी वह कांस्य पदक के साथ लौटेंगी।

यह कॉमनवेल्थ गेम्स में उनका पहला पोडियम फिनिश होगा। लवलीना गोल्ड कोस्ट 2018 में क्वार्टरफाइनल में चैंपियन बनीं सैंडी रयान से हार गई थीं और बर्मिंघम 2022 में अपना पहला ही मुकाबला हार गई थीं। उन्होंने पिछले दोनों इवेंट्स में 69 किग्रा कैटेगरी में हिस्सा लिया था। इस पदक का मतलब यह भी है कि लवलीना ने उन सभी बड़े मल्टी-स्पोर्ट इवेंट्स में पदक जीत लिए हैं जिनमें वह हिस्सा लेने की पात्र थीं। इसमें ओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स शामिल हैं। गुरुवार को ओपनिंग सेरेमनी के लिए जब भारतीय दल शानदार कपड़ों में मैदान पर उतरेगा, तो लवलीना और टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली वेटलिफ्टर मीराबाई चानू फ्लैग और बैटन बियरर लेकर चलेंगी। लवलीना ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य और 2023 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा, उन्होंने चीन के हांगझोउ में हुए 2023 एशियाई खेलों में भी रजत पदक जीता।

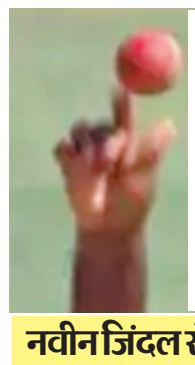

पूर्व क्रिकेटर राजेश चौहान पर लाखों ठगी का आरोप

नवीन जिंदल से पहचान बताकर काम में पार्टनर बनाने ठेकेदार को फंसाया

दुर्ग-भिलाई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पूर्व भारतीय क्रिकेटर राजेश चौहान पर 17.52 लाख रुपए की कथित धोखाधड़ी का आरोप लगा है। जिंदल इस्पात लिमिटेड में ट्रांसपोर्ट का काम दिलाने का झांसा देकर ठेकेदार से फ्रॉड किया गया। अब कोर्ट ने उन पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। पीड़ित दिनकर विश्वमित्र का कहना है कि, राजेश चौहान ने खुद को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर बताते हुए उद्योगपति नवीन जिंदल से करीबी संबंध होने का दावा किया था। भरोसा दिलाने के लिए जिंदल इस्पात का कथित वर्क ऑर्डर भी दिखाया और ट्रांसपोर्ट के काम में पार्टनर बनाने की बात कही। बाद में पता चला कि पूरा दस्तावेज फर्जी था। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अब न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) कोर्ट ने मोहन नगर पुलिस को केस दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया है।

कौन हैं राजेश चौहान?

राजेश चौहान भारत के पूर्व ऑफ स्पिन गेंदबाज हैं। उन्होंने 1993 से 1998 के बीच भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया। घरेलू क्रिकेट में मध्य प्रदेश के लिए शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें भारतीय टीम में जगह मिली। 90 के दशक में वे अनिल कुंबले और वेंकटपति राजू के साथ भारत की स्पिन तिकड़ी का अहम हिस्सा रहे।

- **दोस्त के जरिए हुई पहचान, करोड़ों के काम का दिया लालच-** पीड़ित दिनकर विश्वमित्र ने कोर्ट में बताया कि, उसकी मुलाकात दोस्त सरोज कुमार के जरिए राजेश चौहान से हुई थी। बातचीत के दौरान राजेश ने कहा कि उसकी गोविंद ट्रांसपोर्ट कंपनी को ओडिशा के क्योंझर स्थित जिंदल इस्पात लिमिटेड में आयरन और अन्य सामग्री के ट्रांसपोर्ट का बड़ा ठेका मिला है। अगर वह ट्रक लगाकर इस काम में पार्टनर बनता है, तो उसे अच्छा मुनाफा मिलेगा। भरोसा बढ़ाने के लिए आरोपी ने जिंदल इस्पात का कथित वर्क ऑर्डर और दूसरे दस्तावेज भी दिखाए। इन्हें देखकर दिनकर ने साझेदारी के लिए हामी भर दी।

- **इकरारनामा हुआ, फिर अलग-अलग किस्तों में लिए 17.52 लाख रुपए-** शिकायत के अनुसार, 30 जुलाई 2021 को दोनों पक्षों के बीच इकरारनामा हुआ। उसी दौरान दिनकर ने 2.51 लाख रुपए का पहला भुगतान किया। इसके बाद आरोपी के कहने पर गोविंद ट्रांसपोर्ट कंपनी के खाते में दो किस्तों में 15.01 लाख रुपए और ट्रांसफर कर दिए। इस तरह आरोपी ने कुल 17.52 लाख रुपए ले लिए। पीड़ित को भरोसा था कि जल्द ही ट्रांसपोर्ट का काम शुरू होगा, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी न तो काम मिला और न ही किसी तरह का फायदा।

पॉजिटिव सेल्फ टॉक ने हालैंड को बनाया सुपर स्टार

अर्लिंग हालेंड ने बताया- थकान सिर्फ दिमाग में होती है; विज्ञान भी यही कहता है

न्यूयॉर्क। फुटबाल वर्ल्ड कप में 6 फुट 5 इंच लंबे अर्लिंग हालेंड की फुर्ती और फिटनेस भी चर्चा में रही। उनकी इस शानदार परफॉरमेंस का राज केवल उनकी शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि उनकी गजब की मानसिक मजबूती है।- फुटबाल वर्ल्ड कप में 6 फुट 5 इंच लंबे अर्लिंग हालेंड की फुर्ती और फिटनेस भी चर्चा में रही। उनकी इस शानदार परफॉरमेंस का राज केवल उनकी शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि उनकी गजब की मानसिक मजबूती है।

हालिया फुटबॉल वर्ल्ड कप में नॉर्वे के अर्लिंग हालेंड 7 गोल दागकर टूर्नामेंट के चौथे सबसे सफल खिलाड़ी रहे। 6 फुट 5 इंच लंबे इस खिलाड़ी की फुर्ती और फिटनेस भी चर्चा में रही। उनकी इस शानदार परफॉरमेंस का राज केवल उनकी शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि उनकी गजब की मानसिक मजबूती है। पिछले साल की एक घटना है, जब मैनचेस्टर सिटी की ट्रेनिंग फैसिलिटी में हालेंड एक 'हाइपोक्सिक चैंबर' में एक्सरसाइज बाइक चला रहे थे। यह एक ऐसा कमरा होता है, जहां पहाड़ों जैसी ऊंचाई और तेज गर्मी का माहौल बनाकर हवा में ऑक्सीजन काफी कम कर दी जाती है। हालेंड को पूरी ताकत लगाकर अपना हार्ट रेट 150 बीट्स प्रति मिनट तक ले जाना था।

उन्होंने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा था कि वह यह बिल्कुल नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी करेंगे क्योंकि यह उनके शरीर और दिमाग दोनों के लिए अच्छा है।

वेस्टइंडीज ने आखिरी वनडे 2 विकेट से जीता

न्यूजीलैंड के खिलाफ 2-3 से सीरीज गंवाई, हेटमायर की फिफ्टी

ब्रिजटाउन। मेजबान वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी मैच में 2 विकेट की जीत हासिल की। हालांकि, बुधवार को मिली इस जीत के बावजूद टीम ने 5 मैचों की सीरीज 2-3 से गंवा दी। ब्रिजटाउन में कैरेबियाई टीम ने 269 रन का टारगेट 47.3 ओवर में 8 विकेट खोकर हासिल कर लिया। शिमरोन हेटमायर ने नाबाद 69 रनों की पारी खेली। वे प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। जॉयडन लेनिक्स को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया।

न्यूजीलैंड की खराब शुरुआत- टॉस हराने के बाद पहले बैटिंग कर रही न्यूजीलैंड 50 ओवर में 9 विकेट पर 268 रन बनाए। टीम ने 16 रन के स्कोर पर पहला विकेट गंवा दिया था। यहां पर हेनरी निकोलस 10 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें मैथ्यू फोर्ड ने बोल्ड किया।

यंग-केली ने पारी संभाली, दोनों की फिफ्टी- 5वें ओवर में पहला विकेट गंवाने के बाद ओपनर विल यंग और निक केली ने कीवियों की पारी संभाली। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 90 गेंद पर 86 रन की साझेदारी की। इस साझेदारी को विटेल लुईस ने विल यंग को बोल्ड करके तोड़ा। विल यंग ने 56 रन बनाए। यंग के आउट होने के बाद केली ने मार्क चैपमैन के साथ पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन चैपमैन 11 रन बनाकर आउट हो गए। चैपमैन के आउट होने के बाद विल यंग 64 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।

टॉम लैथम ने स्कोर 200 पार पहुंचाया- मार्क चैपमैन के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे टॉम लैथम ने न्यूजीलैंड की पारी को 200 पार पहुंचा दिया। उन्होंने 69 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली। आखिर में कप्तान मिचेल सैंटनर और नाथन स्मिथ ने 50 ओवर में टीम का स्कोर 268/9 पहुंचा दिया। विटेल लुइस और अल्जारी जोसेफ को दो-दो विकेट मिले।

कैरेबियाई ओपनर्स में फिफ्टी पार्टनरशिप 269 रन का टारगेट चेज करने उतरे कैरेबियाई ओपनर्स ने फिफ्टी पार्टनरशिप की। हालांकि, 59 रन के टीम स्कोर पर पवेलियन भी लौट गए। एकीम ऑगस्टे 34 और जस्टिन ग्रीव्स 22 रन बनाकर आउट हुए। केसी कर्टी 20 और कप्तान शाई होप 39 रन बनाकर आउट हुए।

मैदान पर भावुक हुए मेसी के लिए अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन ने लिखा खास पोस्ट

'आपके आंसू हमारे आंसू हैं'

नई दिल्ली। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना को स्पेन के खिलाफ 0-1 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही टीम का लगातार दूसरी बार खिताब जीतने का सपना अधूरा रह गया। खिताबी मुकाबले में हार के बाद कप्तान लियोनेल मेसी भावुक नजर आए। इस बीच, अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन (एएफए) ने कप्तान मेसी के लिए खास पोस्ट लिखा है। स्पेन के खिलाफ फाइनल मैच में मेसी लय में दिखाई नहीं दिए और विपक्षी टीम ने उन्हें गोल करने का कोई मौका नहीं दिया। अपने प्रदर्शन और खिताबी मुकाबले में मिली हार से मेसी खुद की भावनाओं पर काबू नहीं रख सके। मेसी के लिए अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'कप्तान, आपके आंसू हमारे आंसू हैं। आपने हमें जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां दीं। आपके समर्पण, उस जादू और आखिरी पल तक अपना सब कुछ झोंक देने के लिए आपका शुक्रिया। हम आपसे हमेशा प्यार करेंगे, लियो।' लियोनेल मेसी का प्रदर्शन फीफा वर्ल्ड कप 2026 में शानदार रहा। उन्होंने टूर्नामेंट में कुल 8 गोल और चार असिस्ट किए। मेसी ने सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ अर्जेंटीना को मिली जीत में अहम भूमिका निभाई। मेसी ने इस विश्व कप में कई बड़े रिकॉर्ड्स को भी अपने नाम किया। मेसी विश्व कप इतिहास में सबसे ज्यादा असिस्ट (12) करने वाले खिलाड़ी बने।

उन्होंने इस मामले में पूर्व दिग्गज खिलाड़ी पेले (10) को पीछे छोड़ा। वह तीन विश्व कप के फाइनल में खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने। मेसी अपनी कप्तानी में अर्जेंटीना को फाइनल तक पहुंचाने वाले पहले कप्तान बने। वह विश्व कप के फाइनल में खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बने। स्पेन के खिलाफ मेसी 39 साल और 25 दिन की उम्र में मैदान पर उतरे। मेसी ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप (छह) खेलने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया।

ED का जुर्माना रद्द

ललित मोदी 16 साल बाद भारत लौटेंगे

IPL का पैसा विदेश भेजने का केस; बोले- मैं लीग की भलाई चाहता था

नई दिल्ली। आईपीएल के संस्थापक ललित मोदी 16 साल बाद भारत लौटने की तैयारी में हैं। एक अपीलीय ट्रिब्यूनल ने 16 जुलाई को आईपीएल 2009 के दक्षिण अफ्रीका आयोजन से जुड़े FEMA मामले में फैसला सुनाया था। इसमें मोदी को राहत देते हुए ED के लगाए गए जुर्माने को रद्द कर दिया था। फैसले के बाद ललित मोदी ने कहा कि अब उनकी भारत वापसी का रास्ता साफ हो गया है और वह इस साल के आखिर या अगले साल की शुरुआत में भारत लौट सकते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी अक्टूबर में बच्चे को जन्म देने वाली है, जिसके बाद वह भारत आने की योजना बना रहे हैं।

2018 में लगा था 10.65 करोड़ रुपए का जुर्माना

ED ने 2018 में ललित मोदी पर 10.65 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। इसके बाद उन्होंने इस आदेश के खिलाफ अलग-अलग अपील दायर की थीं। अब 16 जुलाई के फैसले में ट्रिब्यूनल ने उन आदेशों में बड़ा बदलाव करते हुए ललित मोदी समेत कई पक्षों को राहत दे दी।

भारत से दक्षिण अफ्रीका पैसे भेजने का मामला था- यह मामला 2009 में IPL को भारत से दक्षिण अफ्रीका ले जाने से जुड़ा है। उस समय लोकसभा चुनाव के कारण सुरक्षा कारणों से टूर्नामेंट भारत से दक्षिण अफ्रीका शिफ्ट किया गया था। इसके आयोजन के लिए BCCI ने दक्षिण अफ्रीका में करीब 243.45 करोड़ रुपए भेजे थे। बाद में प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया कि यह रकम भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व मंजूरी के बिना विदेश भेजी गई, जिससे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) का उल्लंघन हुआ।

ट्रिब्यूनल बोली-

ललित व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार नहीं- ललित मोदी ने कहा कि ट्रिब्यूनल ने ED की सबसे अहम दलील ही खारिज कर दी, जिससे पूरे मामले का आधार बदल गया। उनके मुताबिक अपीलीय ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा कि दक्षिण अफ्रीका भेजी गई रकम 'करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन' थी, न कि 'कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन'। इसलिए इसके लिए RBI की पहले से मंजूरी लेना जरूरी नहीं था। ट्रिब्यूनल ने यह भी माना कि वह BCCI की ओर से FEMA के तहत कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं थे और न ही उनके पास वह वित्तीय अधिकार थे, जिनका श्रेष्ठ ने दावा किया था। इससे 2009 के दक्षिण अफ्रीका IPL से जुड़े सबसे बड़े कानूनी मामले का अंत हो गया।

स्वामी मुद्रक व प्रकाशक अन्नपूर्णा गुप्ता द्वारा भास्कर प्रिंटिंग प्रेस प्लांट नं. 535 एवं 1272, लालगुटवा रातू पुलिस स्टेशन रांची में मुद्रित तथा विजय जनरल स्टोर, हिनू चौक रांची-834002 से प्रकाशित समस्त दिवानी विवाद न्यायोचित एवं दंडित परिवादों के लिए क्षेत्राधिकारी रांची न्यायालय में रहेगा। पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के जिम्मेदार। **प्रधान संपादक**-अन्नपूर्णा गुप्ता, कार्यालय नं.0651-2253830,मो.9471717919, 7895244551 ईमेलः alagpahchan@gmail.com, www.alagpahchan.com पोस्टल रजिस्ट्रेशन 2013 JHAHINO0575 RNI No.JHAHIN(2013) 66670